



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27112020-223364
CG-MH-E-27112020-223364

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2020/ अग्रहायण 4, 1942

No. 529]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 17 नवम्बर, 2020

संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी .—महापत्रन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा पारादीप पत्रन न्यास (पीपीटी) में मरीनीकृत ईक्यू बर्थ संख्या 1, 2 और 3 के प्रचालन के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण करते समय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित 21 फरवरी, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी में अशुद्धियों के सुधार के लिए पारादीप ईस्ट क्वे कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पीईक्यूसीटीपीएल) द्वारा किये गए अभ्यावेदन का निपटान, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी

पारादीप ईस्ट क्वे कोक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

— — —

आवेदक

गणपूर्ति:

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्टूबर, 2020 के 28वें दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) में मशीनीकृत ईक्यू बर्थ संख्या 1, 2 और 3 के प्रचालन के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण करते समय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित 21 फरवरी 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी में अशुद्धियों के सुधार के लिए परादीप ईस्ट क्वे कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पीईक्यूसीटीपीएल) द्वारा किये गए अभ्यावेदन से संबंधित है।

2.1 पीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण ने 14 जुलाई 2008 के आदेश संख्या टीएएमपी/31/2008-पीपीटी के द्वारा अप्रॉट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में निर्धारित अनुबद्धताओं के आधार पर पीपीटी में एक गहरे डुबाव वाली लौह अयस्क बर्थ और गहरे डुबाव वाली कोयला बर्थ के निर्माण और परिचालन के लिए अप्रॉट प्रशुल्क निर्धारित किये थे।

2.2. तत्पश्चात्, पीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 में निर्धारित अनुबद्धताओं के आधार पर पीपीटी में मशीनीकृत ईक्यू बर्थ संख्या 1, 2 और 3 के प्रचालन के लिए इस प्राधिकरण ने 21 फरवरी 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के द्वारा संदर्भ प्रशुल्क नियत किये। फरवरी 2014 में इस प्रकार निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश में अनुबद्ध उपबंधों के आधार पर गहरे डुबाव वाली कोयला बर्थ के लिए वर्ष 2008 में अनुमोदित अप्रॉट प्रशुल्क पर 26.15% के सूचकांकन गुणक को लागू करने के पश्चात् किया गया था।

3. इसके पश्चात्, पीपीटी ने परियोजना सफल बोली कर्ता को अवार्ड कर दी और पीपीटी तथा परादीप ईस्ट क्वे कोक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पीईक्यूसीटीपीएल) के बीच 2 मई 2016 को एक रियायत करार (सीए) पर हस्ताक्षर हुए।

4.1. इस पृष्ठभूमि में, पीईक्यूसीटीपीएल ने 18 जुलाई 2020 के अपने ई-मेल में निम्नलिखित निवेदन किये:

- (i). पीईक्यूसीटीपीएल और पीपीटी में हस्ताक्षरित रियायत करार के अनुसार बीओटी के अंतर्गत ईक्यू 1,2,3 बर्थों के निर्माण। मशीनीकरण की उन्नत स्थिति में है। कार्य पूरे वेग से चल रहा है और परियोजना कार्य समापन की ओर बढ़ रही है।
- (ii). लेकिन इस प्राधिकरण के लिए पत्तन न्यास और प्राधिकरण द्वारा सुविचारित किन्हीं कारकों के कारण से आदेश में अनभिप्रेत अशुद्धियां रह गई हैं, जिसके कारण पीईक्यूसीटीपीएल को काफी कम निशुल्क दिनों और अत्यधिक उच्च भंडारण दरों के संबंध में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- (iii). पीपीटी ने 2008 में कोयला आयात टर्मिनल के लिए प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण ने 'विभिन्न अवधि ग्रुपों' पर भंडारण प्रभार निर्धारित करते हुए 16 अगस्त, 2008 को अधिसूचना जारी की (राजपत्र संख्या 133) (उदाहरण के लिए 11 से 15 दिन की अवधि के 5 दिन के स्लैब के लिए 12 रु. प्रति एमटी के लिए)।
- (iv). पीपीटी ने 2008 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को संदर्भ के रूप में लिया और 23 जनवरी 2014 को निर्यात कोयला टर्मिनल के प्रशुल्क निर्धारण का प्रस्तुत किया तथा अपने 13 फरवरी 2014 के पत्र के द्वारा उसे अद्यतन किया। पीपीटी प्रस्ताव के आधार पर, प्राधिकरण ने 2008 की आयात टर्मिनल की अधिसूचना के संदर्भ में इस परियोजना के लिए 19 मई 2014 की राजस्व अधिसूचना संख्या 138 के द्वारा प्रशुल्क और अन्य प्रतिमानों का निर्धारण किया।

(v). अधिसूचना राजपत्र संख्या 138 जारी करते समय, यह भली-भांति समझ में आया था कि प्रशुल्क और संबंधित प्रभारों के निर्धारण का आधार 16 अगस्त, 2008 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 133 थी। लेकिन, पीपीटी और प्राधिकरण दोनों ने ही अपने निर्णय लेने में कुछेक गलत संकल्पनाएं की जो परियोजना के लिए हानिकारक थी। ऐसी अशुद्धियां, यदि सुधारी न जाएं, तो वे इस टर्मिनल को व्यवहारिक रूप से किसी भी प्रयोक्ता के लिए अनुपयुक्त बना देती हैं और सारा निवेश तत्काल एनपीए बन जायेगा। ऐसी त्रुटिपूर्ण संकल्पनाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं:-

(क). प्राधिकरण की अधिसूचना (जीएन 133), जिसे पीपीटी और प्राधिकरण ने 2014 में परियोजना को अधिसूचित करने के लिए आधार के रूप में प्रयोग में लिया था जो एक कोयला आयात टर्मिनल के लिए थी। जबकि चालू परियोजना एक निर्माण टर्मिनल है। चूंकि आयात और निर्यात व्यापार के प्रतिमानों में एक भारी अंतर होता है, कार्गो ठहराव समय और भंडारण प्रभारों जैसी संकल्पनाओं के लिए आधार काफी भिन्न और क्रियाशील होते हैं।

(ख). प्राधिकरण की 2008 की अधिसूचना (जीएन 133) 10 एमटीपीए कोयला आयात टर्मिनल के लिए थी जबकि चालू परियोजना 30 एमटीपीए निर्यात टर्मिनल है। 30 एमटीपीए और 10 एमटीपीए के बीच अत्यधिक भिन्नता होती है और आधार संकल्पनाओं का समुचित रूप से मिलान नहीं किया गया है। यह भी कि पत्तन न्यास द्वारा 30 एमटीपीए कार्गो प्रहस्तन के प्रचालन प्रतिमानों की व्यवहार्यता का समुचित रूप से पालन नहीं किया गया।

(ग). प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए प्रशुल्क निर्धारण आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीपी द्वारा किया गया जिसमें प्राधिकरण ने 2008 में अधिसूचित प्रशुल्क पर 26.15% डब्ल्यूपीआई सूचकांकन लागू किया है। लेकिन प्राधिकरण और पत्तन न्यास ने गलती से भंडारण प्रभार में “भिन्न अवधि ग्रुप” के स्थान पर “प्रति दिन प्रति एमटी” जोड़ दिया जिससे भंडारण प्रभारों में बिना किसी कारण अथवा आधार के डब्ल्यूपीआई सूचकांकन के अतिरिक्त 500% तक वृद्धि हो गई। उक्त अशुद्धि की वजह से स्फीति का दो बार और संचयी स्फीति सूचक भंडारण प्रभार के लिए 630% हो गया। ऐसे अपसामान्य भंडारण प्रभारों से, हमारे साथ कोई भी ग्राहक कार्गो प्रहस्तन करार करने को तैयार नहीं है, यह एक काफी भयप्रद स्थिति है। निर्धारित प्रभार भारत में कहीं भी और विदेश में भी पीपीपी पत्तनों में भंडारण के लिए अभूतपूर्व है।

(घ). भारत सरकार के अपक्रंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2008 के अनुसार, कार्गो प्रहस्तन प्रभारों और भंडारण प्रभारों से कुल राजस्व अपेक्षा का संविभाजन क्रमशः 98:1 के अनुपात में होना चाहिए। लेकिन, 2014 में अधिसूचित भंडारण प्रभार, भंडारण से राजस्व 10-15 गुणा अधिक होगा (अशुद्धि के कारण) जो प्राधिकरण के 2008 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं [देखें प्राधिकरण दिशानिर्देश 2008, अनुलग्नक-III, पैरा (2)]।

(ङ). भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी कोयला टर्मिनल के लिए निशुल्क भंडारण अवधि 25 दिन होनी चाहिए और भंडारण प्रभार उस निशुल्क अवधि के बाद ही लागू होंगे। परंतु इस परियोजना में, निशुल्क भंडारण के लिये मात्र 10 दिन ही दिये गये हैं जो प्राधिकरण के प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 का उल्लंघन है। [देखें प्राधिकरण 2008 दिशानिर्देश अनुलग्नक - III, पैरा(2)]।

(च). पारादीप में कोयला टर्मिनल की उपलब्धता के अभाव में, पीपीटी और प्राधिकरण दोनों ने ही स्वीकार किया कि विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (पीपीटी) के टर्मिनल ईक्यू-1क (आदेश संख्या टीएएमपी/53/2009/पीपीटी) से सामान्य निबंधन और शर्तें (टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के प्रशुल्क आदेश, पैरा 4.2.ii में उल्लिखित) का संदर्भ लिया जाये। लेकिन, अशुद्ध संकल्पनाओं के कारण, एक तुलना में, पारादीप कोयला टर्मिनल पर लागू भंडारण प्रभार विज़ॅग टर्मिनल ईक्यू-1क के भंडारण प्रभारों का 940% है जैसा नीचे दर्शाया गया है, जो भारत सरकार के संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रशुल्क प्राधिकरणों तथा पत्तन न्यासों की अपनी संकल्पनाओं का घोर उल्लंघन है, जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

(दर रु. में प्रति टन प्रति दिन या उसका एक भाग)

वस्तु	निशुल्क अवधि के पश्चात् शेष बचे कार्गों के लिए पहले 5 दिन के लिए	शेष कार्गो पर 6वें से 10वें दिन के लिए दर	शेष कार्गो पर 11वें दिन और से दर
ईक्यू-1क विजाग पत्तन न्यास स्टीम	1.61	3.22	6.44
ईक्यू 1-3 पारादीप पत्तन न्यास कोयला	15.15	30.28	60.55
तुलना %	941%	940%	940%

(छ). 30 एमटीपीए निर्यात टर्मिनल के प्रशुल्क निर्धारण के दौरान, प्राधिकरण ने किसी प्रयोक्ता बैठक का आयोजन नहीं किया और इसलिए प्रयोक्ता की शिकायतों को सुना नहीं गया था अतः सुधार नहीं हुआ जो कि भारत सरकार प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित है।

(ज). प्राधिकरण के आदेश में, भंडारण और अन्य टर्मिनल क्षमताओं का परिकलन करते समय, यह मान लिया गया है कि 80% कार्गों के प्रथम साइज़ में होगा और शेष 20% पैनामैक्स आकार के पोतों में होगा। वास्तव में ईक्यू 1-3 बर्थ की गहरायी केवल 15 मीटर है और टिमनल अभी के प्रथम के अनुकूल नहीं है तथा सभी भंडारण यार्ड क्षमता आकलन वास्तविक अवसंरचना के अनुसार नहीं है।

(झ). भंडारण और टर्मिनल क्षमताएं निकालने के लिए टर्न अराउंड अनुपात 12 गुणा के स्थान पर (भारत सरकार द्वारा विनिष्ट एक मानक) 30 गुणा तक ऊचा सुविचार में ले लिया गया है, जिसका कोई आधार नहीं है सिवाए 30 एमटीपीए क्षमता का मिलान करने के लिए।

(vi). इस प्रकार, पीपीटी और प्राधिकरण ने प्रशुल्क निर्धारण में कुछ अशुद्ध संकल्पनाएं की हैं। प्राधिकरण की अधिसूचना में निर्धारित टर्मिनल भंडारण प्रभार सामान्य भंडारण प्रभारों से 1000-1500% अधिक है और ग्राहक इन्हें भारी प्रभारों को कभी सह नहीं पायेंगे।

(vii) ऐसी स्थिति में, ग्राहक इनी भारी लागतों को वहन करने के इच्छूक नहीं होंगे और वे टर्मिनल का कर्तव्य प्रयोग नहीं करेंगे। अतः टर्मिनल में पहले ही दिन से किसी कार्गो की आवाजाही नहीं होगी। सबसे अत्याधुनिक आस्ति पहले ही दिन से न केवल एक एनपीए बन जायेगी बल्कि इसे गंभीर आपूर्ति चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि पारादीप पत्तन दक्षिण भारत के तटीय आवाजाही के लिए कोयले का एक बड़ा मुख्यद्वार है। दक्षिण भारतीय तट में विद्युत संयंत्रों में, जैसे एपीजीईएनसीओ तथा टीएनईबी, संभावित बड़े प्रयोक्ता होंगे और वे कोयले की आवाजाही के लिए पूरी तरह से पारादीप पर निर्भर हैं। अपसामान्य रूप से अधिक भंडारण प्रभार, यदि लागू हो गये तो, इनसे न केवल विद्युत संयंत्रों की पहले से ही बड़ी लागतों को और बढ़ायेंगे बल्कि पारादीप पत्तन के माध्यम से कोयला की

आवाजाही से आर्थिक व्यवहार्यता को भी जोखिम में डाल देगी, परिणाम में पारादीप पत्तन न्यास को राजस्व की हानि तो होगी ही साथ ही साथ अत्याधुनिक कोयला टर्मिनल भी एक एनपीए बन जायेगा।

4.2. इस प्रकार, पीईक्यूसीटीपीएल ने प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के (जैसा प्राधिकरण दिशानिर्देश 2008 अनुलग्नक-III, पैरा 2 में उपबंधित है) विश्वि और कार्यदांचे के भीतर फरवरी 2014 के आदेश की समीक्षा और अशुद्धि सुधार करने का अनुरोध किया है जैसी नीचे बतायी गई है:-

- (i). भंडारण से वार्षिक राजस्व टर्मिनल के कुल वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का 1% होना चाहिए।
- (ii). निशुल्क भंडारण अवधि 10 दिन की जगह 25 दिन की जाए।
- (iii). अन्य प्रचालन प्रतिमानों की समीक्षा की जाये और वास्तविकताओं के अनुसार सही किया जाये।

5.1. पीईक्यूसीटीपीएल के 18 जुलाई 2020 के अभ्यावेदन की एक प्रति टिप्पणियों के लिए लाइसेंस प्रदाता पत्तन (पीपीपी) को भेजी गई। इस संबंध में पीपीटी ने 21 अगस्त, 2020 के पत्र के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये:-

- (i). पीपीटी की बर्थ ईक्यू- 1, 2, 3 के मशीनीकरण के प्रशुल्क आदेश संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के अंतर्गत 21 फरवरी 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी द्वारा किये गए थे। उपरोक्त को अपनाये जाने के पृष्ठभूमि तथ्य प्रशुल्क आदेश में ही कालक्रमानुसार विस्तार से दिये गए हैं।
- (ii). जहां तक भंडारण प्रभार, उगाही की यूनिट और निशुल्क भंडारण अवधि आदि का संबंध है, निम्नवत् तथ्य प्रस्तुत हैं:-
- (क). प्राधिकरण के 21.02.2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी का हवाला देते हुए विनिर्दिष्ट लागू प्रशुल्कों पर बोलियो मंगवाई गई थी। लागू भंडारण प्रभार, उगाही की यूनिट, निशुल्क भंडारण अवधि आदि प्राधिकरण के उक्त आदेश में अनुबद्ध हैं।
- (ख). इस तथ्य पर सुविचार करते हुए कि प्राधिकरण का 21.02.2014 के उक्त आदेश को बोली चरण में ही साफ तौर पर विनिर्दिष्ट किया गया था और बाद में उसका हवाला रियायत करार में भी दिया गया कि प्रशुल्क आदेश में उल्लिखित भंडारण प्रभार से संबंधित व्यैरा अविभावी होगा और उसका पालन होगा।
- (iii). ऊपर कमांक 2 में दिये गए तथ्यों के आलोक में प्राधिकरण के 21 फरवरी 2014 में दर्शाये गए लागू भंडारण प्रभारों, उगाही की यूनिट और निशुल्क भंडारण अवधि में किसी परिवर्तन को बोली पश्च परिवर्तन समझा जाये जो सुग्राही प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किये जाने के कार्यक्षेत्र के बाहर का मामला है।

5.2. पीपीटी की उक्त टिप्पणियों को पीईक्यूसीटीपीएल को हमारे 1 अक्तूबर 2020 के ई-मेल के द्वारा उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। बाद में 15 अक्तूबर, 2020 के अनुस्मारक के पश्चात् पीईक्यूसीटीएल ने 20 अक्तूबर, 2020 के ई-मेल द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये:

- (i). कि यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण के 2008 के आदेश की तुलना में प्राधिकरण के 2014 के आदेश में प्रशुल्क की भंडारण प्रभार यूनिट में “रु. प्रति टन” से “रु. प्रति टन प्रति दिन” की अनभिप्रेत और मिश्या निरूपण अशुद्धि हुई है। हम यह विश्वास करते हैं कि प्राधिकरण के पास अशुद्धियों की समीक्षा और उन्हें ठीक करने की शक्तियां हैं, अतः हम प्राधिकरण को उन्हें ठीक करने का अनुरोध करते हैं।
- (ii). कि इन अशुद्धियों ने डब्ल्यूआईपी को 26.15% से 530% तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से भंडारण प्रभार असहनीय हो गए हैं।
- (iii). कि बोली के लिए प्रयोग की गई प्राधिकरण की 2014 की अधिसूचना (जीएन 138) का आधार प्राधिकरण 2008 की अधिसूचना (जीएन 133) है और प्रशुल्क में डब्ल्यूपीआई स्फीति को 26.15% को ही लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त यह भी सच है कि प्राधिकरण की 2008 की अधिसूचना (जीएन 133) महापत्तन न्यास में पीपीपी परियोजनाओं के अपक्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 (इसे यहां

अब प्राधिकरण 2008 दिशानिर्देश कहा जायेगा) पर आधारित है। अतः “प्राधिकरण दिशानिर्देश 2008” पूरी तरह से लागू हैं और पीईक्यूसीटीएल परियोजना द्वारा भी इनका अनुपालन किया जाना चाहिए। प्राधिकरण दिशानिर्देश 2008, पृष्ठ 11, अनुलग्नक-III। यह बताता है कि प्रशुल्क ढांचा निम्नवत् होना चाहिए:-

“1.0 प्रशुल्क ढांचा

एक मशीनीकृत कोयला टर्मिनल में प्रदत्त सेवाओं को प्रशुल्क ढांचे को निम्नवत् 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- (1) कोयला प्रहस्तन प्रभार
- (2) भंडारण प्रभार
- (3) विविध प्रभार

2.0 कुल राजस्व अपेक्षा के संविभाजन के मानक:

इन दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व अपेक्षा को निम्नलिखित ढंग से उक्त मुख्य प्रशुल्क वर्गों में संविभाजित किया जाता है और प्रत्येक ग्रुप के अंतर्गत व्यक्तिकृत प्रशुल्क मदों का निर्धारण किया जा सकता है।

प्रशुल्क ग्रुप	कुल आबंटित राजस्व का प्रतिशत
कोयला प्रहस्तन प्रभार*	98
भंडारण प्रभार**	1
विविध प्रभार	1

* उक्त मानक इस आधार पर निर्धारित किये जाते हैं कि कोयला प्रहस्तन प्रभार एक मिश्रित प्रभार है जिसमें वैगनों से कोयले की उत्तराई के प्रभार, एक निर्धारित अवधि के लिए यार्ड में भंडारण, कोयला लदान टर्मिनल के लिए जलयान पर लदान और जलयान से उत्तरायी, एक निर्धारित अवधि के लिए यार्ड में भंडारण और कोयला उत्तरायी टर्मिनल के लिए वैगनों/ट्रकों में लदान सेवाएं शामिल हैं।

** भंडारण प्रभार कोयले के यार्ड में 25 दिन की अनुमत अवधि से इतर भंडारण के प्रभार होते हैं।”

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राधिकरण 2008 दिशानिर्देश पीईक्यूसीटीपीएल के प्रशुल्क निर्धारण में मुख्य संदर्भ बिंदु है और इसे पारादीप पत्तन न्यास, प्राधिकरण या बीओटी प्रचालक द्वारा अशुद्धियों, गलतफहमियों अथवा कारण चाहे कुछ भी क्यों न हों तथा बोली पूर्व अथवा बोली पश्च चाहे कोई भी चरण क्यों न हो, अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अतः भंडारण प्रभार कुल राजस्व के 1% से अधिक प्रभारित किसी भी राशि के लिए बोली दस्तावेजों में किसी गलती के कारण या फिर किसी अन्य कारण से प्राधिकरण द्वारा या पारादीप पत्तन न्यास द्वारा बाध्य करना न केवल प्राधिकरण 2008 दिशानिर्देश का जानबूझकर अतिक्रमण का प्रयोग होगा बल्कि इससे पत्तन प्रयोक्ताओं को भी नुकसान होगा और परिणाम में पत्तन प्रयोक्ताओं के नैसर्गिक न्याय के मूलभूत अधिकारों को जान बूझ कर कम करने के समान होगा।

पीईक्यूसीटीएल बचनबद्ध है कि यदि प्राधिकरण के आदेश और पारादीप पत्तन न्यास द्वारा अनुमत किया जाये तो यह पत्तन प्रयोक्ताओं से कुल राजस्व के 1% से कुल भी अधिक प्रभारित नहीं करेगा जब तक कि प्राधिकरण आदेश द्वारा अथवा पारादीप पत्तन न्यास से ऐसे प्रशुल्क को प्रभारित करने को बाध्य न किया जाए।

अतः हम प्राधिकरण से अनुरोध करते हैं कि भंडारण प्रभारों और अन्य प्रयोजनीय खंडों की समीक्षा करें और पारादीप पत्तन न्यास की पीईब्यूसीटीएल से कुल भंडारण प्रभार के रूप में कल राजस्व के 1% के आधार पर ही राजस्व हिस्सा मांगने पर सीमित करें, जिसका वह पात्र है। दिशानिर्देशों के अनुसार, पत्तन प्राधिकारी भंडारण प्रभारों के रूप में 1% से अधिक राजस्व हिस्से की मांग नहीं कर सकते।

(iv). कि पत्तन प्रयोक्ताओं ने प्राधिकरण और पारादीप पत्तन न्यास को पीईब्यूसीटीएल में अशुद्धियों और अधिक भंडारण प्रभारों के प्रति अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए पहले ही लिखना आरंभ कर दिया है। वे टर्मिनल का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे और आने वाले वर्षों में ये चिंताएं और बढ़ेंगी क्योंकि पारादीप पत्तन न्यास में क्षमता की बाधाएं बढ़ना जारी रहेंगी।

(v). कि प्राधिकरण वैबसाइट के अनुसार, परामर्शी प्रक्रिया “प्राधिकरण का उद्यम प्रयोक्तानुमुखी होने पर बल देना है इसकी कार्यप्रणाली में सहभागिता प्रक्रिया की प्रधानता रखने के प्रति वचनबद्धता, प्रयोक्ताओं को अपने हितों के संरक्षण के लिए प्रयाप्त अवसर देने के लिए विशेष ध्यान रखना प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिक प्रशुल्क मामलों में निर्णय लेने से पूर्व नैसर्गिक न्यास के हित में पत्तन स्तर पर संयुक्त सुनवाई का आयोजन”

उक्त परामर्शी प्रक्रिया पत्तन प्रयोक्ताओं को अपने हितों के संरक्षण और नैसर्गिक न्याय प्रदान करने के लिए पत्तन प्रयोक्ताओं को अवसर देने की महत्ता का विस्तार से वर्णन करती है। बोली पूर्व और पश्च प्रक्रिया में पत्तन प्रयोक्ताओं की आवाज़ न सुनने से पारादीप पत्तन न्यास और प्राधिकरण न केवल पत्तन प्रयोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि नैसर्गिक न्यास की प्रक्रिया को भी काट रहे हैं। यह सहभागिता प्रणाली और परामर्शी प्रक्रिया का पूरी तरह से अतिक्रमण है।

(vi). प्राधिकरण की वैबसाइट में “किसी मामले अथवा प्रस्ताव की संक्रिया” के अंतर्गत यह साफ तौर पर लिख है कि प्रस्ताव की संक्रिया इस प्रकार होगी:

(क). इच्छुक पक्षों द्वारा बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को बढ़ावा देना

(ख). परामर्शी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, या तो प्राधिकरण के कार्यालय में या पत्तन स्तर पर सुनवाई आयोजित करना आवश्यक होगा

(ग). संक्रिया के लिए एस ओर से यथा अधिकृत सदस्य ऐसे सिद्धांत लागू करेगा और ऐसी पद्धतियां अपनायेगा जिन्हें नैसर्गिक न्यास के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया होगा।

“इस परियोजना के प्रशुल्क निर्धारण प्रस्ताव” की संक्रिया के दौरान, पारादीप पत्तन न्यास और प्राधिकरण ने उक्त प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन नहीं किया, परिणाम में अनभिप्रेत अशुद्धियां हुईं। “प्राधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने” के लिए में, जैसा पैरा (ग) में दिया गया है, हम प्राधिकरण से अनुरोध करते हैं कि वे पत्तन न्यास स्तर पर हाल ही में हुई संयुक्त सुनवाई के दौरान पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों को महत्व दें और अशुद्धियों का सुधार करें ताकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो।

(vii). कि प्राधिकरण की वैबसाइट के अनुसार प्राधिकरण का चार्टर बताता है कि “इस प्राधिकरण को परंतु दरों के अनुप्रयोजन को शासी करने वाली सोपाधिकताएं भी”।

अतः हम यह विश्वास करते हैं कि प्राधिकरण को न केवल प्रशुल्क निर्धारित बल्कि दरों के अनुप्रयोजनों को शासी करने वाली सोधाधिकताओं का विश्लेषण करने तथा सोपाधिकताओं के अनुसार पीपीपी करार के किसी चरण पर रह गई किसी अशुद्धि को ठीक करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं।

(viii). प्राधिकरण के 2013 के दिशानिर्देश पैरा 1.1 का हवाला देते हुए “इसके अतिरिक्त, गैर-महापत्तनों ने बड़ी तीव्रता से विस्तार किया है कार्गो के 40% हिस्से को बाटते हैं। पत्तन क्षेत्र में समान महत्व देने के लिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि महापत्तनों के प्रशुल्क निर्धारण में प्रतिस्पर्धी बाजार शक्तियों को एक बड़ी भूमिका निभाने वी जानी चाहिए। अतः सरकार ने एतद् द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये हैं।”

उक्त से, यह अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि प्राधिकरण 2013 दिशानिर्देश महापत्तनों को और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, यहां तक कि गैर-महापत्तनों के साथ तुलना में भी, पारित किये गए थे। परंतु 530% डब्ल्यूपीआई के लागू होने से पीईक्यूसीटीएल को न केवल प्रतिस्पर्धाहीन बना देता है बल्कि इसे प्रचालन आरंभ होते ही एक एनपीए उम्मीद्वारा भी। इससे भारत सरकार की महापत्तनों को प्रतिस्पर्धी बनाने की मंशा को गहरा धक्का लगेगा।

(ix). कि प्राधिकरण का दृष्टिकोण कथन कहता है कि “दृष्टिकोण: हमारा दृष्टिकोण है कि हम प्रतिस्पर्धी मूल्यों की ओर बढ़े और भारतीय पत्तनों के निष्पादन को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी स्तरों तक ले जाए।” यदि अशुद्धियां जारी रहें और पीईक्यूसीटीपीएल पूरी तरह से प्रतिस्पर्धाहीन बन जाता है तो यह प्राधिकरण के दृष्टिकोण से विपरीत होगा।

(x). प्राधिकरण की वैबसाइट से ‘आरओसीई और वृद्धि गुणक’ खंड के अनुसार 2008 से 2014 तक अनुमत आरओसीई इस प्रकार है:-

आरओसीई और वृद्धि गुणक

क्र.सं.	इन वर्षों में निर्णीत प्रशुल्क मामलों में	आरओसीई
1.	2018-19	16%
2.	2017-18	16%
3.	2016-17	16%
4.	2014-15	16%
5.	2013-14	16%
6.	2012-13	16%
7.	2011-12	16%
8.	2010-11	16%
9.	2009-10	16%
10.	2008-09	16%
11.	2007-08	16%
12.	2006-07	15%

यदि पीईक्यूसीटीपीएल ने अत्यधिक भंडारण प्रभार प्रभारित करना जारी रखा, आरओसीई अनुमत से कहीं अधिक होगा और ग्राहकों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(xi). कि 'संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 की जांच सूची' सुझाती है कि "दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों के सामने विचलन की तुलना, यदि कोई है, निर्धारित मानकों से विचलनों के लिए प्रत्येक का औचित्य और कारण बताते हुए प्रस्ताव करें।"

दिशानिर्देश सुझाते हैं कि यदि कोई विचलन होता है तो उसका प्रशुल्क प्रस्तावों में औचित्यों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। फिर भी, तथापि पारादीप पत्तन न्यास ने भंडारण प्रशुल्क की यूनिट में "रु. प्रति टन" से "रु. प्रति टन प्रति दिन" परिवर्तित करने का और डब्ल्यूपीआई के 26.15% के स्थान पर 530% लागू करने को न तो स्पष्ट किया है और न ही औचित्य बताया है। यह भी कि निशुल्क भंडारण को अवधि बिना किसी औचित्य के 25 से घटा कर 10 दिन करने का भी।

(xii). कि प्राधिकरण की वैबसाइट शिकायत निवारण प्रक्रिया "प्राधिकरण प्रत्तन प्रशुल्कों से संबंधित मामलों पर सुविचारित रिकार्ड के आधार पर या अन्य किसी उचित कारण से हुई अशुद्धियों की समीक्षा के लिए प्रशुल्क आदेशों की समीक्षा करता है।"

अतः एक अपकृत पक्ष, पीईक्यूसीटीपीएल के अपने अधिकार के भीतर है कि वह अशुद्धियों के सुधार के लिए प्राधिकरण को अनुरोध करे और प्राधिकरण को ऐसी अशुद्धियों का सुधार करने की शक्ति प्राप्त है।

(xiii). तदनुसार, यह अनुरोध है कि प्राधिकरण दिशानिर्देशों के (जैसा प्राधिकरण दिशानिर्देश 2008 अनुलग्नक-III, पैरा 2 में उपबंधित है) विधि और कार्यठांचे के भीतर सुधार करे, जैसी नीचे इंगित की गई है:

(क). भंडारण से वार्षिक राजस्व टर्मिनल के कुल वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का 1% होना चाहिए।

(ख). निशुल्क भंडारण अवधि 10 दिन की जगह 25 दिन की जाए।

(ग). अन्य प्रचालन प्रतिमानों की समीक्षा की जाये और वास्तविकताओं के अनुसार सही किया जाये।

6.1. पीईक्यूसीटीपीएल ने प्राधिकरण को अभ्यावेदन देते समय इस मामले में पोत परिवहन मंत्रालय (एएओएस) को भी अभ्यावेदन किया तदनुसार, एमओएस ने 13 अगस्त 2020 के अपने पत्र के द्वारा प्राधिकरण को पीईक्यूसीटीएल द्वारा किये गए अनुरोध की स्थिति बताने को कहा।

6.2. इस संबंध में, एमओएस को 17 अगस्त, 2020 के ई-मेल के द्वारा पीपीटी की टिप्पणियों/इनपुट्स के आधार पर यह संसूचित किया गया कि कार्रवाई एमओएस को जानकारी देते हुए की जायेगी।

6.3. यह भी कि एमओएस ने पीपीटी को संबोधित प्रति प्राधिकरण को प्रेषित, अपने 03 सितंबर, 2020 के पत्र के द्वारा पीपीटी को यह अनुरोध किया कि पीईक्यूसीटीएल द्वारा उठाये गए मुद्दों पर पृष्ठभूमि टिप्पणी और मुद्दा-वार टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

6.4. इस संबंध में, पीपीटी को 10 सितंबर, 2020 के ई-मेल के द्वारा यह अनुरोध किया कि इस मामले पर एमओएस को जारी पत्र की प्रति उपलब्ध कराने को कहा। 13 अक्टूबर, 2020 के अनुस्मारक के पश्चात् एमओएस को भेजे अपने पत्र की प्रति 15 अक्टूबर, 2020 के ई-मेल के द्वारा उपलब्ध करायी।

6.5. पीपीटी द्वारा एमओएस को भेजी गई पृष्ठभूमि टिप्पणी में पीपीटी ने निम्नलिखित बताया:

(i). **मुख्य विशेषताएं**

(क). परियोजना का नाम: पारादीप पत्तन में बीओटी आधार पर बर्थ ईक्यू-1, 2, 3 का मशीनीकरण।

(ख). ग्राही: पारादीप ईस्ट क्वे कोल टर्मिनल प्रा.लि.

(ग). रियायत अवधि : 30 वर्ष (14.12.2017 से 13.12.2047 तक)

(घ). उद्धरत राजस्व हिस्सा : 31.70%.

(ड). कार्गो वस्तु : कोयला निर्यात

(च). क्षमता : 30 एमटीपीए

(ii). **आरएफपी और ग्राही के अभ्यावेदन में अंतर्विष्ट लागू प्रशुल्क**
बोली कर्ताओं को जारी प्रारूप रियायत करार के परिशिष्ट-12 में लागू प्रशुल्कों को अंतर्विष्ट करते हुए बोलियां आमंत्रित की थीं जो नीचे दिये गए हैं:

(क). **कार्गो प्रहस्तन प्रभार:**

क्र.सं.	वस्तु	यूनिट	दर रु. में (रु.)
क.	ताप कोयला	प्रति मीट्रिक टन	164.00

(ख). **बर्थ किराया प्रभार:**
पोत के लिए मास्टरों/स्वामियों/एजेंटों द्वारा संदेय बर्थ किराया प्रभार की दरें निम्नानुसार होंगी:

क्र.सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका एक भाग (रु.)	
		विदेशी गामी पोत	तटीय पोत
1.	सभी पोत	0.93	0.56

(ग). **भंडारण प्रभार :**
निशुल्क से इतर स्टैक यार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडार प्रभार इस प्रकार होगा

(दर रु. प्रति एमटी प्रति दिन)

क्र.सं.	वस्तु	निशुल्क अवधि के पश्चात शेष बचे कार्गो के लिए 5 दिन के हलए दर	शेष कार्गो पर 6ठें से 10वें दिन तक की दर	शेष कार्गो के लिए 11वें दिन और से दर
1.	ताप कोयला	15.14	30.28	60.55

टिप्पणियां:-

(i). 10 निःशुल्क दिन अनुमत किये जायेंगे, निर्यात कार्गो की निःशुल्क अवधि की गणना सामान (कार्गो) की पत्तन परिसर में प्राप्ति की वास्तविक तिथि से आरंभ होगी। निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजन से सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिन और टर्मिनल के अकार्यदिवस शामिल नहीं किये जायेंगे।

- (ii). भंडारण प्रभार, प्रदत्त निःशुल्क दिनों से आगे भंडारण के लिए, टर्मिनल के अकार्य दिवसों और सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों समेत सभी दिनों के लिए देय होंगे।
- (iii). कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए नहीं जुड़ेगा जिसमें टर्मिनल प्रचालक, उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर, उन कारणों से जिनके लिए टर्मिनल प्रचालक को जिम्मेदार ठहराया जा सके, कार्गो सुपुर्द करने/ पोत लदान करने की स्थिति में न हो।
- (iii). ग्राही का अभ्यावेदन उक्त भंडारण प्रभारों को नीचे को संशोधन करने के लिए है।

6.6. जहां तक पीईक्यूसीटीपीएल के निवेदनों पर एमओएस को उनकी टिप्पणियों का संबंध है, पीपीटी ने मुद्दों को दोहराया है, जैसा पीईक्यूसीटीपीएल के अभ्यावेदन पर इस प्राधिकरण को पीपीटी द्वारा दिये गए हैं जिस पर ऊपर पैरा 5.1 में चर्चा की गई है।

7.1. इसी बीच, प्रयोक्ताओं में से एक नामतः एस कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (एसीसीपीएल) ने 24 अगस्त, 2020 के अपने पत्र के द्वारा उल्लेख किया है कि परियोजना के लिए निर्धारित भंडारण प्रभार काफी अधिक हैं और व्यवहारिक नहीं हैं और कि राहत देने के लिए उनमें कोई स्लैब प्रणाली भी उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रयोक्ता ने प्राधिकरण को मामले को देखने और कुछ निशुल्क दिन देते हुए “स्लैब सिस्टम” पर विचार करने अधिक भंडारण अवधि के साथ प्रशुल्क को बढ़ाने का अनुरोध किया। यह भी बताया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पत्तन प्रयोक्ताओं की बैठक बुलाई जाये ताकि परियोजना के लिए संदर्भ प्रशुल्क की अधिसूचना से पूर्व मुद्दे पर उल्लेख किया जा सके (प्राधिकरण की 21 फरवरी 2014 की अधिसूचना)। इस प्रकार, अन्य प्रयोक्ताओं नामतः बाल्टेयर कोल प्राइवेट लिमिटेड, एमबीजी कोमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड से भी उक्त आदेश के द्वारा अनुमोदित ऊचे भंडारण प्रभारों के प्रति और फरवरी 2014 का आदेश जारी करने से पहले प्रयोक्ताओं से परामर्श नहीं किये जाने के प्रति अभ्यावेदन दिये हैं।

7.2. इस संबंध में, यह कहना है कि चूंकि कोयला परियोजना के लिए पीपीटी द्वारा मांगा गया संदर्भ प्रशुल्क संबंधित प्रयोक्ताओं को सुने जाने के पश्चात् पहले से निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क को अपनाये जाने के लिए या और पोत परिवहन मंत्रालय (एम ओ एस) द्वारा जारी संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि प्रयोक्ताओं से परामर्श करने के पश्चात् पहले से अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क को अपनाये जाने का प्रस्ताव पत्तन न्यास करता है तो प्रयोक्ताओं के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 21 फरवरी, 2014 के सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क आदेश अधिसूचित कराने से पहले कोई संयुक्त सुनवाई आयोजित नहीं की गई।

7.3. जैसा अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 3.8.4 में अनुबद्ध है, प्राधिकरण दरमानों के गलत प्रयोजन की पूछताछ कर सकता है। अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 3.8.5 में उपबंध है कि प्राधिकरण इस प्रश्न को जो किसी निजी परिचालक के दरमानों में स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या से उठते हैं और स्थिति कथन निर्णीत कर सकता है।

7.4. इस पृष्ठभूमि में और प्रयोक्ता की यह शिकायत कि उन्हें सुना नहीं जा रहा है, और कुछेक प्रयोक्ताओं द्वारा किये गए अभ्यावेदनों के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

8.1 संदर्भाधीन मामले में, वीडियो कानफ्रेंसिंग के माध्यम से 24 सितंबर, 2020 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। पीईक्यूसीटीपीएल, प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों और पीपीटी ने संयुक्त सुनवाई में अपने-अपने निवेदन रखे।

8.2 इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

9 मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर, निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:-

- (i). पीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 में निर्धारित अनुबद्धताओं के आधार पर पीपीटी में मर्शीनीकृत ईक्य बर्थ संख्या 1,2 और 3 के प्रचालन के लिए इस प्राधिकरण ने 21 फरवरी 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के द्वारा संदर्भ प्रशुल्क नियत किये। फरवरी 2014 में इस प्रकार निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश में अनुबद्ध उपबंधों के आधार पर गहरे डुबाव वाली कोयला बर्थ के लिए वर्ष 2008 में अनुमोदित अप्रक्रिय प्रशुल्क पर 26.15% के सूचकांकन गुणक को लागू करने के पश्चात् किया गया था।
- (ii). पीपीटी ने बीओटी आधार पर नए कोयला टर्मिनल के विकास की परियोजना पारादीप ईस्ट कवे कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पीईक्यूसीटीपीएल) को अवार्ड की और 2 मई 2016 की पीईक्यूसीटीपीएल के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किये। पीईक्यूसीटीपीएल ने सूचित किया कि ईक्यू-1,2,3 बर्थों के निर्माण/मर्शीनीकरण पूरी गति से चल रहा है और वे परियोजना के निर्माण कार्य के समापन के करीब ही हैं।
- (iii). इस पृष्ठभूमि में, पीईक्यूसीटीपीएल ने जुलाई 2020 के अपने अभ्यावेदन में यह बताया कि फरवरी 2014 के आदेश में गहरे डुबाव वाली कोयला बर्थ के लिए फरवरी 2014 के संदर्भ प्रशुल्क आदेश में कुछ गलतियां हैं और इस प्रकार इस प्राधिकरण को इन अशुद्धियों का सुधार करने को कहा। पीईक्यूसीटीपीएल ने बताया कि यदि अशुद्धियों को अनिर्णीत छोड़ दिया गया, तो इसका प्रयोग किसी प्रयोक्ता द्वारा नहीं किया जायेगा और कि सारा निवेश गैर निष्पादन संपत्ति (एनपीए) हो जायेगा। पीईक्यूसीटीपीएल द्वारा बतायी गई प्रत्येक अशुद्धि और उस पर हमारा विश्लेषण पर आगामी पैराओं में चर्चा की जायेगी।
- (iv). विश्लेषण आरंभ करने से पूर्व, यह बताया जाता है कि 21 फरवरी 2014 के आदेश के द्वारा इस परियोजना के प्रशुल्क निर्धारण प्रस्ताव की प्रक्रिया के दौरान, पीपीटी और इस प्राधिकरण ने परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया, इसलिए फरवरी 2014 के आदेश में अनभिप्रेत अशुद्धियां हुईं। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि चूंकि कोयला परियोजना के लिए पीपीटी द्वारा मांगा गया संदर्भ प्रशुल्क संबंधित प्रयोक्ताओं को सुने जाने के पश्चात् पहले से निर्धारित अप्रक्रिय प्रशुल्क को अपनाये जाने के लिए या और पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि प्रयोक्ताओं से परामर्श करने के पश्चात् पहले से अनुमोदित अप्रक्रिय प्रशुल्क को अपनाये जाने का प्रस्ताव पत्तन न्यास करता है तो प्रयोक्ताओं के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 21 फरवरी, 2014 के सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क आदेश अधिसूचित कराने से पहले कोई संयुक्त सुनवाई आयोजित नहीं की गई। यहां यह विचारणीय है कि यद्यपि इस परियोजना के लिए संदर्भ प्रशुल्क 21 फरवरी, 2014 के आदेश द्वारा निर्धारित किये गए थे, ये प्रशुल्क बोली दस्तावेजों का एक भाग बने थे। किसी भी बोली कर्ता ने उस समय 'तथाकथित अशुद्धियों' का उल्लेख नहीं किया।
- (v). **10 एमटीपीए कोयला आयात टर्मिनल और 30 एमटीपीए निर्यात टर्मिनल की चालू परियोजना के अप्रक्रिय प्रशुल्क की तुलना**

(क). पीईक्यूसीटीपीएल द्वारा किया गया निवेदन:

प्राधिकरण की 2008 की अधिसूचना 10 एमटीपीए कोयला आयात टर्मिनल के लिए थी जबकि चालू परियोजना 30 एमटीपीए निर्यात टर्मिनल है। 30 एमटीपीए और 10 एमटीपीए के बीच

अत्यधिक अंतर है और आधार संकल्पनाओं को समुचित रूप से मिलाया नहीं गया है। 30 एमटीपीए निकासी के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख). विश्लेषण:

जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश के द्वारा अपफ्रंट प्रशुल्क सीमाएं 10 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की इष्टतम क्षमता के कोयला टर्मिनल के लिए निर्धारित की गई थीं। तत्पश्चात्, जब पीपीटी को अपनी कोयला बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क की आवश्यकता थी, इसने आरंभ में आधार प्रशुल्क के रूप में विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) स्थित कोयला प्रहस्तन सुविधा के लिए निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क को अपनाने का प्रस्ताव किया। बाद में, वीपीटी की परियोजना के लिए निर्धारित प्रशुल्क को अपनाएं जाने के बारे में पीपीटी को भेजे गए एक संदर्भ का उत्तर देते समय, पीपीटी ने ईक्यू- 1,2, और 3 बर्थों के मशीनीकरण के संदर्भ प्रशुल्क निकालने के लिए जुलाई 2008 में गहरे डुबाव कोयला बर्थ के मामले में निर्धारित अपने स्वयं के अपफ्रंट प्रशुल्क अपनाने का अनुरोध किया। संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के खंड 2.2 और 2.4 में यह अपेक्षित है कि पत्तन किसी भी अपफ्रंट प्रशुल्क को आधार मानकर उन्हें अपना सकता है, केवल तभी जब ये विकास के लिए प्रस्तावित परियोजना का निरूपण करते हों। यह बताये जाने पर कि पत्तन ने स्वयं अपने प्रशुल्क को ही आधार के रूप में चयन करना चाहा है, दिशानिर्देश इस प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं समझते और कि इस प्राधिकरण के लिए भी कोई ऐसा कारण नहीं है कि वह पीपीटी द्वारा विकसित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे की गहरायी तक जाये। इस संबंध में, इस प्राधिकरण ने फरवरी 2014 के आदेश में रिकार्ड किया है कि प्रस्तावित सुविधा में ताप कोयला प्रहस्तन के संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण के लिए गहरे डुबाव वाली कोयला बर्थ के मामले में ताप कोयले के लिए निर्धारित अपने स्वयं के अपफ्रंट प्रशुल्क अपनाये जाने के संबंध पत्तन के निर्णय पर विश्वास किया गया था। 10 एमटीपीए कोयला आयात टर्मिनल के लिए अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क को 30 एमटीपीए कोयला निर्यात टर्मिनल में लागू करने का निर्णय पीपीटी का था।

(vi). धांक ऊंचाई और प्लॉट टर्न ओवर अनुपात :

(क). पीईक्यूसीटीएल द्वारा किया गया निवेदन:

दिशानिर्देशों में दिये गए मानकों के अनुसार, प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 3 टन कोयला स्टैक किया जा सकेगा। पीपीटी द्वारा इस गुणक को जुलाई 2008 के अपफ्रंट आदेश में 4.7 टन पर सुविचार में लिया। इसके अतिरिक्त, प्लॉट टर्नओवर अनुपात भी दिशानिर्देशों में दिये गए मानकों के अनुसार 12 के स्थान पर 30 को सुविचार में लिया। इतना ऊँचा औसत टर्न अराउंड अनुपात विश्व में अथवा भारत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। 30 का टर्न अराउंड अनुपात निकालने के लिए न तो किसी निकासी मॉडल पर सुविचार किया गया और न ही कोई ग्राहक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया। दिशानिर्देशों में दिये गए प्रतिमानों पर सविचार किया जाए।

(ख). विश्लेषण:

पीपीटी के प्रस्ताव में, जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में परिणत होते समय, पीपीटी ने 4.7 मीट्रिक टन/वर्ग मीटर की स्टैकिंग क्षमता का और प्लॉट टर्न अराउंड अनुपात के रूप में 30 पर सुविचार किया गया था। यह अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित 3 मीट्रिक टन/ वर्ग मीटर की स्टैकिंग क्षमता और 12 के प्लॉट टर्न अराउंड अनुपात के मानक से भिन्न है। यद्यपि,

जुलाई 2008 के अप्रूंट प्रशुल्क आदेश के समय की गई परामर्श प्रक्रिया में, प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने यह कहते हुए आपत्तियां की थी कि यह विकासक के लिए हानिकारक होगा, पीपीटी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि अपने स्वयं के मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन में तापीय और कोकिंग कोयले की काफी बड़ी मात्रा पहले ही प्रहस्त कर रहा है और कोकिंग कोयले में 4 मीट्रिक टन/वर्ग मीटर की स्टैकिंग क्षमता तथा ताप कोयले के लिए 5.4 मीट्रिक टन/वर्ग मीटर की स्टैकिंग क्षमता प्राप्त कर चुका है। इसी प्रकार, पीपीटी ने बताया था कि पीपीटी के स्वयं के कोयला प्रहस्तन प्लॉट में वह 21.3 टर्नओवर प्राप्त कर चुका है। अतः तदनुसार पत्तन ने 4.7 मीट्रिक टन/वर्ग मीटर की औसत पर स्टैकिंग ऊंचाई और 30 के प्लॉट टर्न ओवर पर विचार किया था जो विशिष्ट रूप से धरातल पर वास्तविकता और साथ्यकी आकड़ों पर आधारित निर्णय था। अप्रूंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 3.2 इस प्राधिकरण को संबंधित पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत औचित्यों के आधार पर तथा पत्तन विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखकर दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों में आवश्यक समंजन करने की अनुमति देता है।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 4.7 मीट्रिक टन/वर्ग मीटर की स्टैकिंग क्षमता और 30 का प्लॉट टर्न ओवर अनुपात पीपीटी का एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय था और इस संबंध में कोई गलती नहीं हुई है। इसलिए पीईक्यूसीटीपीएल की इस दलील में कोई जान नहीं है कि स्टैकिंग क्षमता और प्लॉट टर्न अराउंड अनुपात पर दिशानिर्देशों के अनुसार सुविचार किया जाए।

(vii). निःशुल्क दिनः

(क). पीईक्यूसीटीपीएल द्वारा किया गया निवेदनः

प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुसार किसी कोयला टर्मिनल के लिए निःशुल्क भंडारण अवधि 25 दिन होनी चाहिए और भंडारण प्रभार उस निःशुल्क अवधि के बाद ही लागू होंगे। परंतु इस परियोजना में, निःशुल्क भंडारण प्रभार मात्र 10 दिन ही दिये गये हैं जो प्राधिकरण के प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 का उल्लंघन है और इससे भंडारण प्रशुल्क में कृत्रिम रूप से 2-3 गुणा बढ़ोत्तरी हो गई। हाल ही के सप्ताह में पारादीप पत्तन में, अत्यधिक प्लॉट शेष के साथ 25-30 दिन का ठहराव समय था, परिणाम में 1000/-रु. एमटी का प्लॉट किराया पड़ा।

(ख). विश्लेषणः

जुलाई 2008 अप्रूंट प्रशुल्क आदेश में परिणत होने वले पीपीटी के प्रस्ताव में पीपीटी ने 10 दिन की निःशुल्क अवधि पर सुविचार किया है जो अप्रूंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में यथा अनुबद्ध 25 दिनों से भिन्न था। पीपीटी के अनुसार, उत्तरायी का काम पूरा होने के बाद मानकों में यथा अनुबद्ध 25 दिन की निःशुल्क अवधि देना अनिवार्य नहीं था क्योंकि पीपीटी के स्वयं के मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र ने 21.3 का टर्नओवर प्राप्त किया था। तदनुसार, पत्तन द्वारा यथाप्रस्तावित 30 के उच्च टर्न ओवर अनुपात को ध्यान में रखते हुए, पीपीटी द्वारा 10 दिन की निःशुल्क अवधि का प्रस्ताव किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि मानकों में यथाअनुबद्ध 25 दिन की निःशुल्क अवधि इस बात को ध्यान में रखे बिना निर्धारित की गई थी कि कोयला टर्मिनल चाहे निर्यातीन्मुखी है या आयातोन्मुखी। अप्रूंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 3.2 इस प्राधिकरण को संबंधित पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत औचित्यों के आधार पर तथा पत्तन विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखकर दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों में आवश्यक समंजन करने की अनुमति देता है।

बोली पूर्व बैठक के दौरान विभिन्न संभावित बोली कर्ताओं द्वारा उठाये गए प्रश्नों (जो पीपीटी द्वारा पीईक्यूसीटीएल के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार का एक भाग है) में, पीपीटी ने, कुछक प्रश्नों के उत्तर में, सूचित किया कि निःशुल्क अवधि 10 दिन है जो उस समय पत्तन में मौजूदा कोयल निर्यात टर्मिनल में प्रचलित निःशुल्क दिवसों पर सुविचार करने के बाद रखी गई है।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 10 दिन की निःशुल्क अवधि पर सुविचार करने का पीपीटी का एक भली-भांति सोच विचार कर लिया गया निर्णय था। अतः पीईक्यूसीटीएल की ओर से यह कहना ठीक नहीं है कि पीपीटी ने 10 दिन की निःशुल्क अवधि को सुविचार में लेने के कोई कारण नहीं बनाए हैं। इसलिए, इस बारे में कोई गलती नहीं हुई है, पीईक्यूसीटीपीएल द्वारा रखी गई दलील में कि दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार निःशुल्क दिवसों पर विचार करने का कोई मेरिट नहीं है।

तिस पर भी, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें अधिकतम दर होती है और प्रचालक कम दर प्रभारित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, पीईक्यूसीटीएल के पास पूरी छूट है कि वह निर्धारित 10 दिन के स्थान पर अधिक निःशुल्क दिवस दे सकता है।

जहां तक पीईक्यूसीटीपीएल द्वारा पीपीटी को संदेय राजस्व हिस्से का संबंध है, यह बताया जाता है कि एमओएस ने 11 जुलाई 2018 के अपने पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष में महापत्तन न्यासों में पीपीपी परियोजना को तंगहाल परियोजना के रूप में वर्गीकृत करने की एक कसौटी निर्धारित की है। उक्त पत्र में यह प्रणाली भी बतायी गई है भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकृत किये जाने वाले राजस्व हिस्से का भुगतान कैसे किया जाये अर्थात् जब तंगहाल पीपीपी परियोजना के लिए भंडारण प्रभार कम कर दिया जाये अथवा निःशुल्क अवधि को बढ़ा दिया जाये। उक्त पत्र में दिया गया सिद्धांत यह कि बीओटी प्रचालक को भंडारण प्रभार से प्राप्त वास्तविक राजस्व पर रियायत करार के अनुसार स्वीकृत दर पर अथवा मूल आदेश में आकलित भंडारण प्रभारों से, वार्षिक सूचकांकन लागू करने के पश्चात्, एआरआर पर परिकलित राजस्व हिस्से का, जो भी अवधि हो, भुगतान करना होगा। वास्तव में, एमओएस ने 11 जुलाई 18 के अपने उक्त पत्र में इस प्राधिकरण के 11 दिसंबर, 2015 के पत्र का हवाला दिया है जिसमें इस प्राधिकरण ने एमओएस को उच्च भंडारण प्रभार से संबंधित विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (पीपीटी) की परियोजनाओं में से एक मामले में इन्हीं लाइनों पर यह सिफारिश की थी।

अतः पीपीटी और पीईक्यूसीटीएल भंडारण प्रभार पर राजस्व हिस्से के भुगतान के बारे में परस्पर चर्चा करक तंगहाल परियोजनाओं पर एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने पर सुविचार करें।

(viii). केपसाइज और पैनामैक्स पोतों का मिश्रण:

(क). पीईक्यूसीटीएल द्वारा किया गया निवेदन:

प्राधिकरण के आदेश में भंडारण और अन्य टर्मिनल क्षमताओं की गणना करते समय यह संकल्पना की गई कि 80% कार्गो केपसाइज में और 20% कार्गो पैनामैक्स आकार के पोत में आयेगा। वास्तव में, ईक्यू 1,2, और 3 ब्रूथ की गहरायी 15 मीटर है और टर्मिनल अभी केप के

अनुकूल नहीं है यानी इसका डुबाव इतना नहीं है कि यह अभी केप आकार के पोतों को प्रहस्त कर सके। इसलिए, केपसाइज और पेनामैक्स पोतों के मिश्रण का 80:20 अनुपात सही नहीं है।

(ख). विश्लेषण:

जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में केपसाइज और पेनामैक्स पोतों के क्रमशः 80:20 के मिश्रित पोतों को सुविचार में लेते हुए अपफ्रंट प्रशुल्क कैप्स निर्धारित किये गए। जैसा पहले बताया गया है, पत्तन ने ईक्यू-1.2 और 3 बर्थों के मशीनीकरण के संदर्भ प्रशुल्क निकालने के लिए अपने स्वयं के ही प्रशुल्क को ही आधार मानक अपनाने का निर्णय लिया। दिशानिर्देश भी इस प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं करते और न ही इस प्राधिकरण को पीपीटी द्वारा विकसित की जा रही प्रस्तावित सुविधा के ब्यौरे का गहनता से सुविचार करने का कोई कारण नज़र आता है। प्रशुल्क परियोजना के लिए बोली निकाले जाने से पहले ही, अपफ्रंट दिये गए थे। ऐसी स्थिति में, अब टर्मिनल की क्षमता की समीक्षा करने का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए यह प्राधिकरण इस संबंध में पीईक्यूसीटीएल द्वारा रखी गई दलील पर सुविचार करने की स्थिति में नहीं है।

(ix). **प्रभारण प्रभार :**

(क). पीईक्यूसीटीपीएल द्वारा किया गया निवेदन:

प्राधिकरण ने इस प्ररियोजना के लिए प्रशुल्क निर्धारित आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी द्वारा किया गया जिसमें प्राधिकरण ने 2008 में अधिसूचित प्रशुल्क पर 26.15% डब्ल्यूपीआई सूचकांकन लागू किया है। लेकिन प्राधिकरण और पत्तन न्यास ने गलती से भंडारण प्रभार में “भिन्न अवधि ग्रुप” के स्थान पर “प्रति दिन प्रति एमटी” जोड़ दिया जिससे भंडारण प्रभारों में बिना किसी कारण अथवा आधार के डब्ल्यूपीआई सूचकांकन के अतिरिक्त 500% तक वृद्धि हो गई। उक्त अशुद्धि की वजह स्फीति का दो बार और संचयी स्फीति सूचक भंडारण प्रभार के लिए 630% हो गया। ऐसे अपसामान्य भंडारण प्रभारों से, हमारे साथ कोई भी ग्राहक कारोगी प्रहस्तन करार करने को तैयार नहीं है, यह एक काफी भयप्रद स्थिति है। निर्धारित प्रभार भारत में कहीं भी और विदेश में भी पीपीटी पत्तनों में भंडारण के लिए अभूतपूर्व है।

(ख). विश्लेषण:

(i). 14 जुलाई 2008 के आदेश में, जो कोलया बर्थ के संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 21 फरवरी 2014 के संदर्भ प्रशुल्क आदेश के आधार बने हैं भंडारण प्रभार के लिए उगाही की यूनिट कोयल प्रहस्तन के लिए ‘प्रति टन’ की निर्धारित की गई थी। लेकिन जुलाई 2008 के आदेश के आधार पर सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण का अनुमोदन चाहते समय, पीपीटी ने भंडारण प्रभार के लिए उगाही की यूनिट ‘प्रति टन प्रति दिन’ आधार पर प्रस्तावित की थी जो 21 फरवरी, 2014 के सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क आदेश में अनजाने में आ गई।

(ii). नीचे दी गई सारणी, इस स्थिति को दर्शाती है:-

विवरण	भंडारण प्रभारों की उगाही दर	निशुल्क अवधि के पश्चात शेष बचे कार्गो के लिए 5 दिन के लिए दर	शेष कार्गो पर 6ठें से 10वें दिन तक की दर	शेष कार्गो के लिए 11वें दिन और से दर
14 जुलाई 2008 के आदेश में अनुमोदित	दर प्रति टन में	12	24	48
26.15%का सूचकांकन लागू करने के पश्चात, 21 फरवरी, 2014 के आदेश द्वारा अनुमोदित	दर रु. में प्रति टन प्रति दिन	15.14	30.28	60.55

इस प्रकार, फरवरी 2014 के आदेश में, यद्यपि भंडारण प्रभार जुलाई 2008 के आदेश में अनुमोदित भंडारण प्रभारों पर 26.15% के सूचकांकन गुणक लागू करने के पश्चात् निर्धारित किये गए थे, भंडारण प्रभारों की उगाही की यूनिट 'प्रति टन' के स्थान पर 'प्रति टन प्रति दिन' आधार पर निर्धारित हो गई। उक्त अशुद्धि न तो इस प्राधिकरण के ध्यान में आयी और न ही उस समय किसी और की भी ध्यान इस पर गया। यह केवल तभी प्रकाश में आयी जब इसके कार्यान्वयन का समय निकट आया।

(iii). संयुक्त सुनवाई के दौरान पीईक्यूसीटीपीएल ने इस अशुद्धि के परिणामों के बारे में उदाहरण देकर समझाया जैसा इस कार्यसूची टिप्पण में पहले चर्चा की जा चुकी है। वर्ष 2020-21 के लिए सूचकांकित भंडारण दर 10 दिन के निःशुल्क ठहराव समय के पश्चात् प्रयोक्ता को 17.21 रु. प्रति टन प्रति दिन 34.43 रु. प्रति टन प्रति दिन और तीसरे स्लैब के लिए 68.86 रु. प्रति टन प्रति दिन के हिसाब से भुगतान करने होंगे। दिन वार कार्गो के आधार पर 3350 टन प्रति दिन कार्गो परेषण के 30 दिन के लिए वह कार्गो 31वें दिन वदान होगा, तो प्रयोक्ता को 10 दिन की निशुल्क अवधि का लाभ उठाने के बाद 3.34 करोड़ रु. की राशि का भुगतान करना होगा। जब भंडारण प्रभार 'प्रति टन प्रति दिन' आधार पर परिकलित किया जाता है तो भंडारण प्रभार 62.16 करोड़ रु. बनता है। ऐसे परिणामों की प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में अपेक्षा नहीं की गई है।

(iv). अतः यदि प्रचालक को 'प्रति टन प्रति दिन' आधार पर भंडारण प्रभारों की उगाही की अनुमति दी जाती है तो दृष्टांत उदाहरण के अनुसार उसे 3.34 करोड़ रु. मिलेंगे। 3.34 करोड़ रु. पर पीपीटी भी राजस्व हिस्से का पात्र होगा। यह प्राधिकरण के साथ-साथ पत्तन को, पत्तन प्रयोक्ताओं की लागत पर एक अन्यायपूर्ण प्रतिफल होगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। टर्मिनल भंडारण प्रभारों के रूप में राजस्व अर्जन के लिए परिचालित नहीं किये जाते।

(v). इसके अतिरिक्त, अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश, 2008 के अनुसार टर्मिनल परिचालन से कुल 100% की राजस्व अपेक्षा का मात्र 1% की दर से भंडारण प्रभारों से राजस्व अपेक्षा का संविभाजन भी होगा। जुलाई 2008 में अपफ्रंट प्रशुल्क का निर्धारण करते समय 10 दिन की निःशुल्क अवधि के बाद 11वें से 15 वें दिन, 16वें से 20वें दिन और 21वें दिन तथा उससे आगे जो कार्गो भंडारण में पड़ा रहेगा उस पर 12/-रु., 24/-रु. और 48/-रु. प्रति टन की दर से भंडारण प्रभारों की वसूली करने के प्रस्ताव के आधार पर 131 लाख रु. तक की राजस्व अपेक्षा की गई थी। लेकिन, पीईक्यूसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत गणना के अनुसार, पीईक्यूसीटीपीएल ने स्थापित किया है कि सूचकांकित भंडारण प्रभार प्रति टन प्रति दिन आधार पर लगाये जाने से इसे इतनी अत्यधिक भंडारण आय हो जायेगी कि वह 16% के अनुमत प्रतिफल से भी ज्यादा कम लेगा। प्रति टन प्रति दिन की दर से भंडारण प्रभारों की उगाही करने से पीईक्यूसीटीपीएल के साथ-साथ पीपीटी भी नियोजित पूँजी पर, पत्तन प्रयोक्ताओं की लागत पर, अन्यायपूर्ण आय अर्जित करेंगे।

(vi). चूंकि पीपीटी ने 21 फरवरी, 2014 के आदेश संब्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी को विनिर्दिष्ट करते हुए बोलियां आमंत्रित की थीं, जिसमें भंडारण प्रभार उगाही की यूनिट “प्रति एमटी प्रति दिन” दी गई है। पीपीटी का तर्क यह है कि भंडारण प्रभार की उगाही की यूनिट को ‘प्रति टन, प्रति दिन’ से “प्रति टन” किये जाने को बोली पश्च परिवर्तन समझा जायेगा। इस संबंध में, पीईक्यूसीटीपीएल ने बताया है कि पीईक्यूसीटीपीएल के लिए प्रशुल्क निर्धारण करने के लिए मुख्य संदर्भ विषय प्राधिकरण के 2008 के दिशानिर्देश हैं और अशुद्धियों, गलतफहमियों अथवा चाहे कुछ भी हो, और इस बात पर ध्यान दिये बिना भी कि चरण भी चाहे कोई सा भी हो, यानी बोली पूर्व या बोली पश्च, उनको पीपीटी, प्राधिकरण अथवा पीपीपी प्रचालक किसी के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। यह ध्यान देने योग्य है कि फरवरी 2014 का आदेश, जुलाई 2008 के आदेश में निर्धारित प्रशुल्क को सूचकांकन गुणक लागू करने के पश्चात् अपनाया जाना भर था बस और कुछ नहीं और कि भंडारण प्रभार निर्धारित करते समय भंडारण प्रभारों की उगाही की यूनिट निर्धारण में एक अशुद्धि हो ही गई, जिसके सुधार की आवश्यकता है।

(vii). ऐसा भी मत हो सकता है कि महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.8 अनुबद्ध करता है कि इस प्राधिकरण द्वारा एक बार निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क परियोजना की पूरी 30 वर्ष की अवधि के दौरान केवल सूचकांकन के अधीन ही होंगे और कि इस प्राधिकरण निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क में परियोजना अवधि के दौरान संशोधन की कोई गुजाइश नहीं है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि, संदर्भाधीन के मामले में वर्ष 2008 में अपफ्रंट प्रशुल्क में कोई संशोधन प्रभावी नहीं किया गया है और वर्ष 2014 में सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के रूप में अपनाया गया है। फरवरी 2014 के संदर्भ प्रशुल्क आदेश में हो गई एक विसंगति को ही सुधारा जा रहा है। इस अशुद्धि सुधार किसी भी ढंग से इस प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2008/फरवरी 2014 में अनुमोदित अपफ्रंट/ संदर्भ भंडारण प्रभारों में संशोधन किया गया न समझा जाये।

(viii). संयोगवश, इस संबंध में, अन्य महापत्तन में उठे इसी प्रकार के मामले की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है अर्थात् विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के साथ-साथ पीपीटी में एक और परिचालक नामतः जेएसडब्ल्यू पारादीप टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (जेपीटीपीएल) जहां ऐसे मामले उठे थे।

(क). वीपीटी के मामले में, वीपीटी के ईन्नर हार्बर के उत्तर की ओर वेस्ट क्लू-6 (डब्ल्यूक्यू 6) बर्थ के लिए अपक्रंत प्रशुल्क निर्धारण के पश्चात्, वीपीटी ने डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ का विकास कार्य वेस्ट क्लू-6 मल्टीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूक्यूएमपीएल) को डीबीएफओटी आधार पर सौंपा। तत्पश्चात्, डब्ल्यूक्यूएमपीएल ने अपने नाम से दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क किया। डब्ल्यूक्यूएमपीएल के नाम से दरमान अधिसूचित किये गए। बाद में, डब्ल्यूक्यूएमपीएल ने माननीय तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्य के हैदराबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2017 की 28595 में दायर की और, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रार्थना के साथ हस्तक्षेप चाहा कि डब्ल्यूक्यूएमपीएल के मामले में निर्धारित भंडारण प्रभारों को घटाया जाये। माननीय उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2017 के आदेश में इस प्राधिकरण को डब्ल्यूक्यूएमपीएल के अभ्यावेदन पर सुविचार करके निपटाये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने वीपीटी से परामर्श के बाद 18 मई, 2018 को आदेश संख्या टीएएमपी/85/2017-वीपीटी के द्वारा डब्ल्यूक्यूएमपीएल के अभ्यावेदन पर सुविचार किया था और भंडारण प्रभारों का निर्धारण पहले अधिसूचित भंडारण प्रभारों को 7 दिनों से विभक्त करके किया ताकि भंडारण प्रभार “प्रति दिन प्रति टन आधार पर निर्धारित किया जा सके।

(ख). इसी प्रकार, पीपीटी में विकसित की जाने वाली नई लौह अयस्क बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित किये जाने के पश्चात्, पीपीटी ने परियोजना डीबीएफओटी आधार पर जेपीटीपीएल को सौंपी। तत्पश्चात्, जेपीटीपीएल ने अपने नाम से दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क किया। ऐसा करते समय जेबीटीपीएल ने अधिसूचित संदर्भ प्रशुल्क आदेश में भंडारण प्रभारों में रह गई अशुद्धि में सुधार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि भंडारण प्रभार की उगाही की यूनिट में ‘दर रु. प्रति टन प्रति दिन’ के स्थान पर ‘दर रु. में प्रति टन’ किया जाये। परामर्शी प्रक्रिया के पश्चात्, इस प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2020 को अपने आदेश संख्या टीएएमपी/54/2019-जेपीटीपीएल के द्वारा जेपीटीपीएल के नाम से दरमानों को अधिसूचित करते समय भंडारण प्रभारों की उगाही की यूनिट के निर्धारण में अशुद्धि को सुधारा गया।

(ix). वास्तव में, जैसा ऊपर चर्चा की गई है, जेपीटीपीएल के प्रस्ताव का निपटान करते समय, पीपीटी ने परामर्शी प्रक्रिया के दौरान उल्लेख किया था कि जेपीटीपीएल परियोजना के लिए उगाही की यूनिट ‘प्रति टन’ करने से 21 फरवरी 2014 और 22 जनवरी 2017 के प्रशुल्क आदेशों के द्वारा पीपीटी में बर्थ ईक्यू-1, 2 और 3 के मशीनीकरण और आयात कोयला प्रहस्तन के लिए नई कोयला बर्थ से संबंधित पीपीपी परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस प्राधिकरण ने जेपीटीपीएल के प्रस्ताव को

निपटाते समय, जैसा ऊपर बताया है, साफ तौर पर कहा कि पीपीटी का ऐसा तर्क जेपीटीपीएल के भंडारण प्रभारों के निर्धारण में हुई अशुद्धि सुधार के मार्ग का रोड़ा नहीं बन सकता। यदि 21 फरवरी 2014 और 22 जनवरी, 2017 के प्रशुल्क आदेशों में भंडारण प्रभार निर्धारित करते समय यदि कोई अशुद्धि रह जाती है और जब संबंधित परिचालक इस प्राधिकरण को इस विषय में संपर्क करेगा जो उस अशुद्धि का परीक्षण करना होगा पीपीटी के साथ परामर्श से सुधार करना पड़ेगा।

(x). उक्त स्थिति को देखते हुए, यह प्राधिकरण भंडारण प्रभार की उगाही की यूनिट में हुई अशुद्धि का सुधार करने को प्रवृत्त है। अशुद्धि सुधार दो ढंग से किया जा सकता है:

(क). सूचकांकित भंडारण प्रभारों की उगाही की यूनिट 'प्रति टन' निर्धारित करके

अथवा

(ख). इस पर सुविचार करते हुए कि भंडारण प्रभार 5 दिनों के स्लैब में निर्धारित किये गए हैं, प्रस्तावित सूचकांकित भंडारण प्रभारों को 5 से विभक्त करके और सूचकांकित भंडारण प्रभारों की उगाही की यूनिट 'प्रति टन प्रति दिन' निर्धारित की जाए।

इस संबंध में, यह दिया गया है कि भंडारण प्रभार सभी महापत्तन न्यासों के और उनमें परिचालित प्राइवेट टर्मिनलों में समान निर्धारण के रूप में दरमानों में 'प्रति टन प्रति दिन' आधार पर निर्धारित हैं। भंडारण अनुसूची में, निशुल्क ठहराव समय के पश्चात् 3 प्रभार्य स्लैब अवधियां हैं। पहली दो प्रभार्य स्लैब अवधि प्रत्येक 5 दिन के ठहराव समय की है। तीसरा स्लैब 11वें दिन से आरंभ होता है (निशुल्क अवधि के पश्चात्) जो अतिरिक्त काल के लिए है। यदि कार्गो प्रथम दो प्रभार्य स्लैब अवधियों से इतर भी भंडारण यार्ड में रखा रहता है, और यदि उगाही की यूनिट प्रति टन में निर्धारित है, यह संभव है कि प्रयोक्ता कीमती पत्तन परिसर को लंबी अवधि तक आकूपाई रखना जारी रखें। पत्तन परिसर में कार्गो के ठहराव की अवधि चाहे कोई भी हो, प्रयोक्ताओं को पत्तन परिसर में रखे कार्गो की मात्रा के लिए नियत भंडारण प्रभार देने के बाध्य हैं। ऐसी किसी स्थिति में, भंडारण प्रभारों का निर्धारण किसी प्रयोक्ता को लंबे समय तक भंडारण यार्ड के रूप में पत्तन परिसर का प्रयोग करने में हतोत्साहित करेगा और एक बाधक बन कर खड़ा होगा।

इस प्रकार, पीईक्यूसीटीपीएल के मामले में, यह प्राधिकरण अन्य सभी महापत्तनों और अनमें परिचालित बीओटी परिचालकों में भंडारण प्रभार की उगाही की यूनिट के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए भंडारण प्रभार की उगाही की यूनिट के रूप में "प्रति टन प्रति दिन" आधार पर निर्धारित करने को प्रवृत्त है।

(x). पीपीटी की टिप्पणियों का उत्तर देते समय, पीईक्यूसीटीपीएल ने बताया कि यदि इस प्राधिकरण और पीपीटी द्वारा अनुमति दी जायेगी तो यह पत्तन प्रयोक्ताओं से कुल राजस्व के 1% से अधिक कोई भंडारण प्रभार प्रभारित नहीं करेगा। जब तक कि प्राधिकरण अथवा पीपीटी द्वारा ऐसे प्रशुल्क को प्रभारित करने को बाध्य नहीं किया जायेगा। अतः पीईक्यूसीटीपीएल ने इस प्राधिकरण को अनुरोध किया कि भंडारण प्रभार और अन्य अनुप्रयोज्य खंडों की समीक्षा करें और आदेश जारी करें कि पीपीटी को भंडारण प्रभार के रूप में कुल राजस्व के केवल 1% के आधार पर पीईक्यूसीटीपीएल से राजस्व हिस्से की मांग करने तक सीमित करें, जिसके बे पात्र हैं क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार, पीपीटी को भंडारण प्रभार के रूप में एक प्रतिशत से अधिक का राजस्व हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं है।

जहां तक पीईक्यूसीटीपीएल द्वारा पीपीटी को संदेय राजस्व हिस्से का संबंध है, यह बताया जाता है कि एमओएस ने 11 जुलाई 2018 के अपने पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष में महापत्तन न्यासों में पीपीपी परियोजना को तंगहाल परियोजना के रूप में वर्गीकृत करने की एक कसौटी निर्धारित की है। उक्त पत्र में यह प्रणाली भी बतायी गई है भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकृत किये जाने वाले राजस्व हिस्से का भुगतान कैसे किया जाये अर्थात् जब तंगहाल पीपीपी परियोजना के लिए भंडारण प्रभार कम कर दिया जाये अथवा निःशुल्क अवधि को बढ़ा दिया जाये। उक्त पत्र में दिया गया सिद्धांत यह कि बीओटी प्रचालक को भंडारण प्रभार से प्राप्त वास्तविक राजस्व पर रियायत करार के अनुसार स्वीकृत दर पर अथवा मूल आदेश में आकिलित भंडारण प्रभारों से, वार्षिक सूचकांकन लागू करने के पश्चात्, एआरआर पर परिकलित राजस्व हिस्से का, जो भी अवधि हो, भुगतान करना होगा। वास्तव में, एमओएस ने 11 जुलाई 18 के अपने उक्त पत्र में इस प्राधिकरण के 11 दिसंबर, 2015 के पत्र का हवाला दिया है जिसमें इस प्राधिकरण ने एमओएस को उच्च भंडारण प्रभार से संबंधित विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) की परियोजनाओं में से एक मामले में इन्हीं लाइनों पर यह सिफारिश की थी। अतः पीपीटी और पीईक्यूसीटीपीएल भंडारण प्रभार पर राजस्व हिस्से के भुगतान के बारे में परस्पर चर्चा करके तंगहाल परियोजनाओं पर एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने पर सुविचार करें।

10.1. परिणाम में और ऊपर बताये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण भंडारण प्रभारों की उगाही के निर्धारण में हुई अशुद्धि के सुधार के लिए शुद्धि पत्र जारी करने को प्रवृत्त हैं। अतः 21 फरवरी 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के द्वारा अनुमोदित दरमानों के भाग 2.2 में निर्धारित भंडारण प्रभारों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है।

“

(दर रु. में प्रति एमटी प्रति दिन)

क्र.सं.	वस्तु	निःशुल्क अवधि के पश्चात् शेष बचे कार्गों के लिए पहले 5 दिन के लिए दर	शेष कार्गों के लिए 6वें दिन से 10 वें दिन के लिए दर	शेष कार्गों पर 11वें दिन और से दर
1.	ताप कोयला	3.03	6.06	12.11

“

10.2. पीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह उक्त संशोधन का संज्ञान ले।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./389/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th November 2020

No. TAMP/12/2014-PPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (PEQCTL) to rectify the errors in Order no. TAMP/12/2014- PPT dated 21 February 2014 notified by TAMP fixing Reference Tariff for operation of Mechanised EQ berths no. 1, 2 and 3 at Paradip Port Trust (PPT), as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**NO. TAMP/12/2014-PPT****PARADIP EAST QUAY COAL TERMINAL PRIVATE LIMITED**

APPLICANT**QUORUM:**

- (i). Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 28th day of October 2020)

This case relates to the representation made by Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (PEQCTL) to rectify the errors in the Order no. TAMP/12/2014- PPT dated 21 February 2014 notified by this Authority fixing Reference Tariff for operation of Mechanised EQ berths no. 1, 2 and 3 at Paradip Port Trust (PPT).

2.1 Based on a proposal filed by PPT, this Authority vide its Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008 had fixed upfront tariff for construction and operation of a deep draught iron ore berth and a deep draught coal berth at the PPT, based on the stipulations prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008.

2.2. Thereafter, based on a proposal filed by PPT, this Authority vide its Order no. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014 fixed Reference tariff for operation of Mechanised EQ Berth nos. – 1, 2, 3 at the PPT, based on the stipulations prescribed in the Reference Tariff Guidelines of 2013. The Reference tariff so fixed in February 2014 was after applying an indexation factor of 26.15% over the upfront tariff approved in the year 2008 for the deep draught coal berth, based on the enabling provisions stipulated in Reference Tariff Guidelines of 2013.

3. Subsequent to this, the PPT has awarded the Project to the successful bidder; and, a Concession Agreement (CA) has been signed by PPT with Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (PEQCTL) on 02 May 2016.

4.1. In this backdrop, the PEQCTL vide its email dated 18 July 2020 has made the following submissions:

- (i). The PEQCTL is in advanced stage of construction/ mechanization of EQ-1, 2, 3 berths under BOT basis as per Concession Agreement signed with PPT. The work is in full swing and approaching towards completion of the project.
- (ii). However, due to some factors considered by the Port Trust and TAMP for this Project, there are inadvertent errors in the Order, due to which PEQCTL is facing severe challenges with respect to very less free days and extremely high Storage Rates.
- (iii). PPT had submitted a proposal to TAMP for fixation of Tariff for coal Import terminal in 2008. Based on the proposal of PPT, the TAMP has issued Notification (G. No 133) dated 16.08.2008, specifying storage charges on "different period groups" (for example: Rs. 12 per MT for 5 days' slab of 11 to 15" days period).
- (iv). The PPT has taken the above mentioned 2008 notification as reference and submitted a proposal to TAMP for setting tariff for Export coal terminal on 23 January, 2014 and updated the same vide its letter dated 13 February 2014. Based on PPT proposal, TAMP has fixed the tariff and other parameters for this project by Gazette Notification No. 138 dated 19 May 2014, keeping the 2008 notification of Import Terminal as reference.
- (v). While releasing the notification G.No.138, it was well understood that the base of setting tariffs and related charges was the Notification vide G.No.133 dated 16 August 2008. However, PPT and TAMP both have inadvertently taken few erroneous assumptions in their judgment which will be detrimental for the project. Such errors, if not resolved, would make this terminal practically not usable by any user, and entire investment will become NPA immediately. A few examples of such erroneous assumptions are as below:
 - (a). TAMP notification in 2008 (GN 133), which PPT and TAMP used as base to notify for the project in 2014, was for an Import Coal terminal, while current project is an Export terminal. Since there is a big difference between export and import

business parameters, base for assumptions such as dwell time of cargo and storage charges are very different and dynamic.

- (b). TAMP 2008 notification (GN 133) was for a 10 MTPA Coal Import Terminal, while current project is a 30 MTPA Export Terminal. There is a substantial difference between the scale of 30MTPA and 10MTPA, and base assumptions are not properly aligned. Also a proper feasibility of operating parameters for 30 MTPA cargo handling were not conducted by the Port Trust.
- (c). TAMP has fixed the tariff for this project by order no. TAMP/12/2014-PPT in which TAMP has applied 26.15% WPI Indexation on tariff notified in 2008. However, TAMP and Port Trust had erroneously added "Per day Per MT" in storage charges instead of "different period groups", which inflated the storage charges by 500% over and above the 26.15% WPI Indexation, without any reasoning and basis. The said error has led to application of inflation twice and cumulative inflation index over 630% for the storage charges. Due to such abnormal storage charges, no customer is willing to sign a cargo handling agreement with us, which is a very alarming situation. The charges specified are unprecedented for storage in the PPP ports anywhere in India and abroad, and have no rationale.
- (d). As per Government of India upfront tariff setting guidelines of 2008, apportionment of Total Revenue Requirement from Cargo handling charges and storage charges should be in proportion of 98:1 respectively. However, the storage charges notified in 2014 circular, the revenue from storage would be 10-15 times more (due to the error) which violates the TAMP 2008 Tariff Guidelines [refer TAMP 2008 Guideline Annexure -III, Para (2)].
- (e). As per Government of India guidelines, free storage days for a coal terminal should be 25 days, and storage charges be applied only after that free period. But in this project, the free storage days provided are only 10 days which violates TAMP 2008 Tariff Guidelines [refer TAMP 2008 Guideline Annexure -III, Para (2)].
- (f). Due to absence of availability of a Coal Terminal at Paradip, PPT and TAMP both agreed to take the reference for General Terms and Conditions (mentioned in tariff order, Para 4.2.ii of TAMP 12/2014-PPT), from EQ-1A terminal of Visakhapatnam Port Trust (VPT) (Order No. TAMP/53/2009/VPT). However, due to erroneous assumptions, in a comparison, the storage charges applied at Paradip Coal Terminal are 940% of the storage charges of EQ-1A Vizag terminal as depicted below, which is a complete violation of Reference Tariff Setting Guidelines of Govt. of India, and Tariff Authorities and Port Trust's own assumptions also, as shown below:

(Rate in Rs. per tonne per day or part thereof)

Commodity	Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after free period	Rate for 6 th day to 10 th day for the balance cargo	Rate for 11 th day onwards for the balance cargo
EQ1- A Vizag Port Trust Steam Coal	1.61	3.22	6.44
EQ 1-3 Paradip Port Trust Coal Terminal	15.15	30.28	60.55
Comparison in %	941%	940%	940%

- (g). During fixation of tariff for 30 MTPA Export terminal, TAMP did not conduct any user meetings, and hence users' grievances were not heard and rectified which is required as per the Government of India Tariff Setting Guidelines.
- (h). In TAMP order, while calculating storage and other terminal capacities, it is assumed that 80% of the cargo will be in Cape size and 20% of the cargo in Panamax size of vessel. In reality, the EQ 1-3 berth depth is only 15 Meters,

and terminal is not yet Cape Compliant, and all storage yard capacity calculations are not as per the actual infrastructure.

- (i). To derive the storage and terminal capacities, turnaround ratio was considered as high as 30 times instead of 12 times (a norm specified by Government of India) without having any basis, and only to match the 30 MTPA Capacity.
- (vi). Thus, PPT and TAMP have made few erroneous assumptions in Tariff setting and storage parameters. Terminal storage charges specified in TAMP notification are 1000-1500% higher than normal storage charges and the customers will never be able to absorb such huge charges.
- (vii) In such a scenario, the customers will not be willing to absorb such huge costs and hence may not use the terminal at all. Thus, the terminal will not see any cargo moving from day one. This will not only make the state of the art asset a NPA from day one, but will also create serious supply chain challenges as Paradip Port being the major gateway of coal for coastal movement to Southern India. Power Plants in Southern India Coast such as APGENCO & TNEB will be potential major users and dependent entirely on Paradip for movement of coal. Abnormally high storage charges, if applied, will not only increase the already rising cost of power plants but will also jeopardize the economic viability of moving coal through Paradip port, resulting in a loss of revenue to the Paradip Port Trust as well as the state of the art coal terminal, a NPA.

4.2. Thus, the PEQCTL has requested to review and rectify the errors in the Order of February 2014 in a manner and framework within the TAMP Guidelines (as provided in TAMP 2008 Guidelines, Annexure III, Para 2) as given below:

- (i). Annual revenue from Storage should be 1% of the Total Annual Revenue Requirement (ARR) of the terminal.
- (ii). Free Storage Period should be allowed 25 days instead of 10 days.
- (iii). Other operating parameters to be reviewed and corrected as per ground realities.

5.1. A copy of the PEQCTL representation dated 18 July 2020 was forwarded to the Licenser port (PPT) for its comments. In this regard, the PPT vide its letter dated 21 August 2020 has made the following submissions:

- (i). Tariff order for Mechanization of EQ - 1, 2, 3 berths at PPT was notified by TAMP vide Order No. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014 under the Reference Tariff Guidelines, 2013. The background facts leading to the adoption of the above is detailed out chronologically in the TAMP Order itself.
- (ii). As regards the storage charges, unit of levy, and free storage period etc., following are the facts:
 - (a). The bids have been invited specifying the applicable tariffs giving reference to TAMP Order No. TAMP/12/2014-PPT dated 21.02.2014. The applicable storage charges, unit of levy, free storage period etc. are stipulated in the said TAMP order.
 - (b). Considering the fact that the above TAMP Order dated 21.02.2014 has been explicitly specified in the bid stage and subsequently reflected in the Concession Agreement, the details relating to storage charges mentioned in Tariff Order shall prevail and be followed.
- (iii). In the light of the facts given above at Sl. No. 2, any changes in the applicable storage charges, unit of levy, free storage period etc. indicated in TAMP order dated 21 February 2014 would be construed as post bid changes beyond the scope of the Concessioning Authority for acceptance.

5.2. The said comments of PPT was forwarded to PEQCTL vide our email dated 1 October 2020 for its comments. Subsequently, after a reminder dated 15 October 2020, the PEQCTL vide its email dated 20 October 2020, has made the following submissions:

- (i). That it is evident that an inadvertent error and misrepresentation has happened in storage charges unit of tariff from "Rs Per Ton" to "Rs Per Ton Per Day", in TAMP 2014 order

compared to TAMP 2008 order. We believe that the TAMP has required powers to review and correct the errors, and hence we request TAMP to correct the same.

- (ii). That the errors have inflated the WIP application from 26.15% to 530%, leading to unbearable storage charges.
- (iii). That the TAMP 2014 notification (GN 138) used for bidding is based on TAMP 2008 notification (GN 133), and only 26.15% WPI inflation was supposed to be updated in tariff. Further it is also true that TAMP 2008 notification (GN 133) is based on Guidelines for upfront tariff setting for PPP Projects at Major Port Trusts, 2008 (referred here as “**TAMP 2008 Guidelines**”). Hence TAMP 2008 Guidelines are fully applicable and should be followed for PEQCTL project also.

Referring to TAMP 2008 Guidelines, page 11, Annexure III, which suggests a tariff structure appended as below:

“1.0 Tariff Structure

The tariff structure for services rendered at a mechanized Coal terminal can be grouped under the following three major groups:

- (1) Coal Handling charges
- (2) Storage charges
- (3) Miscellaneous charges

2.0 Norms for apportionment of total Revenue requirement

The total Revenue requirement determined as per these guidelines is apportioned among the aforesaid major tariff groups in the following manner and rates for individual tariff items under each of the groups can be determined.

Tariff Group	Percentage of total revenue allocated
Coal handling charges*	98
Storage Charges**	1
Miscellaneous Charges	1

* The above norms are prescribed on the basis that the coal handling charges is a composite charge comprising of charges for unloading of coal from wagons, storage at the yard for prescribed period and loading on to ship for coal loading terminal and unloading from ship, storage at the yard for prescribed period and loading onto wagons/trucks for coal unloading terminal.

** Storage charges is the charges levied for storage of coal at the yard beyond allowable period of 25 days.

“

It can be concluded that TAMP 2008 Guidelines is main reference point for setting up of tariff for PEQCTL, and same cannot be breached by Paradip Port Trust, TAMP or PPP Operators by way of errors, misunderstanding or whatsoever the reason may be, and before the bidding or after the bidding whatsoever the stage may be. Hence, storage charges charged by any amount over and above 1% of total revenue, if forced by Paradip Port Trust or TAMP order due to errors in bidding documents or any other reason, will not only be a deliberate attempt to breach the TAMP 2008 Guidelines, but also harm the port users and lead to deliberate curtailment of fundamental rights of natural justice of port users.

PEQCTL commits that if permitted by TAMP order and Paradip Port Trust, it will not charge storage charges from port users anything more than 1% of total revenue, unless otherwise forced by TAMP Order or Paradip Port Trust to charge such tariff.

Hence we request the TAMP Authority to review the storage charges and other applicable clauses, and pass an order restricting the Paradip Port Trust to demand revenue share from PEQCTL based on only 1% of the total Revenue as total storage charges, which it is entitled for. As per the Guidelines, Port Authority does not have any rights to demand revenue share more than 1% as storage charges.

- (iv). That the Port users have already started writing to Tariff Authority and Paradip Port Trust and raising their concerns about the errors and high storage charges at PEQCTL. They will be unable to use the terminal, and these concern will further amplify in coming years, as the capacity constrains at Paradip Port Trust continue to grow.
- (v). That as per TAMP website, Consultative Process "*The endeavor of the Authority is to emphasise user-orientation commitment to let the participative process preponderate in its working, special care is taken to give adequate opportunities for users to represent their interests.....joint-hearings are held at the port level in the interest of natural justice before the Authority decides individual tariff cases*".

The above Consultative Process elaborates the importance of giving opportunities to port users to represent their interests and provide a natural justice. By not hearing the port users voice before the bidding and even after the bidding process, Paradip Port Trust and TAMP will not only harm the port users interest, but also curtail the process of natural justice. It will be a complete breach of participative approach and Consultative Process.

- (vi). That on TAMP website under 'Processing of a case or proposal' section, clearly mentioned that the process of proposal to be followed as:
 - (a). *To promote the greatest participation of the greatest number of interested parties.....*
 - (b). *As part of the consultative process it may be necessary to organise either at the Office of the Authority or at the port level hearings.....*
 - (c). *For processingMembers so authorised in this behalf shall apply such principles and adopt such approaches as may be notified from time to time by the Authority ensuring adherence to the principles of natural justice.*

During the process of the tariff setting proposal for this project, Paradip Port Trust and TAMP did not completely follow the above processes, leading to the inadvertent errors. In the interest of "Authority ensuring adherence to the principle of natural justice" as stated in Para (c), we request authority to give importance to the voice of port users raised during the recent Joint hearing at local Port Trust level and rectify the errors, ensuring the adherence of principle on natural justice.

- (vii). That as per TAMP website, Charter of TAMP states "*His Authority hasbut also the conditionalities governing application of rates*".

Hence we believe that the TAMP is fully empowered for not only to fix the tariff but also to analyse the conditionalities governing application of the rates, and correct any errors at any stage of the PPP agreement as per conditionality.

- (viii). That referring to TAMP 2013 Guideline para 1.1 "*Moreover, non-major ports have since expanded rapidly accounts for about 40% of the cargo share. In order to provide a level playing field in the Port sector, it has become imperative that competitive market forces may be allowed to play a greater role in determination of tariffs at major Ports. Hence, the Government hereby issues the following directions.*"

From above, it can be easily inferred that TAMP 2013 Guidelines were passed to make Major Ports more competitive, even to compare with non-major ports. But the inadvertent error by way of application of 530% WPI will make PEQCTL not only uncompetitive, but also an NPA candidate immediately upon start of operations. It will be a great setback for Government of India's intention to make Major Ports competitive.

- (ix). That TAMP Vision statement states “*Vision: Our vision is to move to competitive pricing and to push performance of Indian Ports to Internationally Competitive Levels.*”. If error continues, and PEQCTL becomes completely uncompetitive, it will be against the vision of the TAMP.
- (x). As per TAMP website ‘ROCE and Escalation Factor’ section, ROCE permitted for year 2008 to 2014 are as below:

ROCE & Escalation factor

Sr. No.	For Tariff Cases decided in the year	ROCE
1.	2018-19	16%
2.	2017-18	16%
3.	2016-17	16%
4.	2014-15	16%
5.	2013-14	16%
6.	2012-13	16%
7.	2011-12	16%
8.	2010-11	16%
9.	2009-10	16%
10.	2008-09	16%
11.	2007-08	16%
12.	2006-07	15%

If PEQCTL continue charging very high storage charges, the ROCE will be much higher than permitted and will lead to legal actions by customers.

- (xi). That the ‘Checklist for Reference Tariff under 2013 guidelines’ suggests that “*Norms prescribed in the guidelines vis-à-vis deviation, if any, proposed there from along with justification and reasons for each of the deviations made from the prescribed norms.*”
-
- The guidelines suggest that in tariff proposals, it is mandatory to propose the justification if any deviation. However, Paradip Port Trust has not clarified or justified the change of unit of tariff for storage from “Rs Per Ton” to Rs Per Ton Per Day” and application of WPI of 530% instead of 26.15%. Also free storage days reduced from 25 to 10 without any justifications.
- (xii). That as per TAMP website Grievance Redressal Process “*TAMP also undertakes review of Tariff Orders for review of errors on the face of records considered and for any other justifiable reason.....on matters relating to port pricing*”.
-
- Hence as an aggrieved party, PEQCTL is within its rights to request TAMP for rectification of errors and TAMP has such powers to rectify the errors.
- (xiii). Accordingly, it is requested to review this matter and rectify the errors in a manner and framework within the TAMP Guidelines (as provided in TAMP 2008 Guidelines, Annexure III, Para 2) as below:
 - (a). Annual revenue from Storage should be 1% of the Total Annual Revenue Requirement (ARR) of the terminal.
 - (b). Free Storage Period should be allowed 25 days instead of 10 days.
 - (c). Other operating parameters should be reviewed and corrected as per ground realities.

6.1. The PEQCTL, while representing to TAMP has also represented to Ministry of Shipping (MOS) on the matter. Accordingly, the MOS vide its letter dated 13 August 2020 requested TAMP to furnish the status of the request made by PEQCTL.

6.2. In this regard, it has been conveyed to the MOS vide email dated 17 August 2020 that based on the comments/ inputs of PPT, necessary action will be taken under intimation to MOS.

6.3. Also, the MOS vide its letter dated 03 September 2020 addressed to PPT and with a copy endorsed to TAMP, has requested PPT to furnish a background note and the point wise comments on the issues raised by PEQCTL.

6.4. In this regard, the PPT was requested vide email dated 10 September 2020 to make available a copy of the letter issued by it to the MOS, on the matter. After a reminder dated 13 October 2020, the PPT vide its email dated 15 October 2020 has forwarded a copy of its response to MOS.

6.5. In the Background Note forwarded by PPT to MOS, the PPT has stated the following:

(i). **Salient features**

- (a). Name of the Project: Mechanization of EQ-1,2,3 berths at Paradip Port on BOT basis.
- (b). Concessionaire: Paradip East Quay Coal Terminal Pvt. Ltd.
- (c). Concession Period: 30 years (14.12.2017-13.12.2047).
- (d). Revenue Share quoted: 31.70%.
- (e). Cargo Commodity: Coal Exports.
- (f). Capacity: 30 MTPA.

(ii). **Applicable Tariffs incorporated in RFP and Concessionaire's Representation**

The RFP bids were invited incorporating the applicable Tariffs in Appendix-12 of the Draft Concession Agreement issued to the bidders given as under.

(a). **Cargo Handling Charges:**

Sr. No.	Commodity	Unit	Rate in Rupees (Rs.)
a.	Thermal Coal	Per Metric Tonne	164.00

(b). **Berth Hire Charges:**

The Berth Hire charges payable by masters/owners/agents for the vessel shall be as per rates below:

Sr. No.	Vessels	Rate per GRT per hour or part thereof (Rs.)	
		Foreign going vessel	Coastal Vessel
1.	All Vessels	0.93	0.56

(c). **Storage Charges:**

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below:

(Rate in ₹ Per MT per day)

Sr. No.	Commodity	Rate for five days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 6th day to 10th day for the balance cargo	Rate for 11th day onwards for the balance cargo
1.	Thermal Coal	15.14	30.28	60.55

N.B.:-

- (i). 10 free days shall be allowed. Free period for export cargo shall commence from the actual date of the receipt of goods in the Port premises. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non- working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- (iii). Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.
- (iii). The Concessionaire's representation is for downward revision of the above storage charges.

6.6. As regard its comments to the MOS on the submissions of PEQCTL, the PPT has reiterated the points, as given by PPT to this Authority on the PEQCTL's representation, as brought out at paragraph 5.1 above.

7.1. In the meanwhile, one of the Users, i.e. Ace Commercial Company Limited (ACCPL) vide its letter 24 August 2020 has pointed out that the storage charges prescribed for the project is very high and not workable and even there is no slab system available thereto to provide relief. The said user has requested TAMP to look into the matter and consider a "Slab System" giving few free days and hike the tariff with higher storage period. It has also indicated that a port users meeting should have been called by TAMP to enable them point out the issue, before notifying reference tariff for the project (TAMP Notification dated 21 February 2014). Likewise, representations have been received from other users viz., Waltair Coal Private Limited, MBG Commodities Private Limited and JSW Energy Limited, representing against the high storage charges approved vide the said Order and the users not being consulted before issue of the Order of February 2014.

7.2. In this regard, it is to state that since the Reference tariff sought by PPT for the coal project was an adoption of the Upfront tariff already fixed after hearing the concerned users and since Reference Tariff Guidelines, 2013 issued by the Ministry of Shipping does not require consultation with the users when a Port Trust proposes to adopt an upfront tariff already approved after consulting the users, no joint hearing was set-up before notifying the Indexed Reference tariff Order dated 21 February 2014.

7.3. As stipulated in Clause 3.8.4 of the Upfront Tariff Guidelines of 2008, TAMP can enquire into wrong application of Scale of Rates. Clause 3.8.5. of the Upfront Tariff Guidelines of 2008 provides that TAMP can decide a question which arises, requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditions of a private operator.

7.4. In this backdrop and in view of the grievance of the user of not being heard and based on the representation made by few users, it was decided to give an opportunity of hearing to the concerned parties.

8.1 A joint hearing on the case in reference was held on 24 September 2020 through Video Conferencing. The PEQCTL, Users/ User Organisations and PPT have made their submissions at the joint hearing.

8.2 The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

9 With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). Based on a proposal filed by Paradip Port Trust (PPT), this Authority vide its Order no. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014 fixed Reference tariff for Mechanization of EQ Berth nos. – 1, 2, 3 at the PPT, based on the stipulations prescribed in the Reference Tariff Guidelines of 2013. The Reference tariff so fixed in February 2014 was after applying an indexation factor of 26.15% over the upfront tariff approved in the year 2008 for the deep draught coal berth, based on the enabling provisions stipulated in Reference Tariff Guidelines of 2013.

- (ii). The PPT has awarded the Project of development of a new Coal terminal on BOT basis to the Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (PEQCTL) and has signed a Concession Agreement (CA) with PEQCTL on 02 May 2016. The PEQCTL has reported that the construction/ mechanization of EQ-1, 2, 3 berths is in full swing and has reported to be approaching towards completion of the project.
- (iii). In this backdrop, the PEQCTL in its representation of July 2020 has pointed out errors in the Reference tariff Order of February 2014 for the deep draught coal berth vide the Order of February 2014 and has thus, requested this Authority to rectify the errors. The PEQCTL has stated that if the errors remain unresolved, it would not be used by any user, and that the entire investment will become a Non-Performing Asset (NPA) immediately. Each of the errors pointed out by PEQCTL and our analysis thereon is discussed in the subsequent paragraphs.
- (iv). Before we begin the analysis, it is to state that the PEQCTL has stated that that during the process of the tariff setting proposal for this project vide the Order dated 21 February 2014, the PPT and this Authority did not follow the consultative process, thereby leading to the inadvertent errors in the Order of February 2014.

In this regard, it is to state that since the Reference tariff sought by PPT for this coal project was an adoption of the Upfront tariff already fixed after hearing the concerned stakeholders and since Reference Tariff Guidelines, 2013 issued by the Ministry of Shipping did not require consultation with the users when a Port Trust proposes to adopt an upfront tariff already approved after following the consultation process, no joint hearing was set-up before notifying the Indexed Reference tariff Order dated 21 February 2014. It is noteworthy that though the Reference tariff for this project fixed vide Order dated 21 February 2014, formed part of the bid documents, none of the bidders have pointed out any of the 'so-called errors' then.

- (v). **Upfront tariff for a 10 MTPA Coal Import Terminal vis-à-vis current project of a 30 MTPA Export Terminal**

(a). Submissions made by PEQCTL:

TAMP notification in 2008 was for a 10 MTPA Coal Import Terminal, while current project is a 30 MTPA Export Terminal. There is a substantial difference between the scale of 30 MTPA and 10 MTPA, and base assumptions are not properly aligned. No feasibility study for evacuation of 30 MTPA was done.

Analysis:

Vide the Upfront tariff Order of July 2008, upfront tariff caps was fixed for coal terminal for an optimal capacity of 10 Million Metric Tonnes Per Annum. Thereafter, when the PPT had wanted a Reference tariff for its Coal berth, it had initially proposed adoption of the upfront tariff fixed in respect of coal handling facility at Visakhapatnam Port Trust (VPT) as a base tariff. Subsequently, while replying to a reference made to PPT on the adoption of the tariff fixed for the project of VPT, the PPT had requested to adopt its own upfront tariff fixed in the case of deep draught coal berth in July 2008 as base, to arrive at the Reference tariff for the Mechanisation of EQ – 1, 2 and 3 berths. Clause 2.2 and 2.4 of the Reference Tariff Guidelines, 2013, requires the port to adopt any upfront tariff as base, only if it represents the project proposed to be developed. Given that the port itself had chosen to adopt its own tariff as base, the Guidelines did not require this Authority and there was no reason for this Authority to delve deep into the details of the project proposed to be developed by PPT. In this connection, this Authority in the Order of February 2014 has recorded that the judgment of the port to adopt its own upfront tariff fixed for thermal coal in the case of the deep draught coal berth to determine the Reference tariff handling thermal coal at the proposed facility, was relied upon. Applying the Reference Tariff approved for 10 MTPA coal import terminal to 30 MTPA coal export terminal was the decision of the PPT.

- (vi). **Stacking height and Plot Turnover ratio:**

(a). Submissions made by PEQCTL:

As per the norms given in the guidelines, coal that could be stacked per sq.m of area is 3 tonnes. This factor has been considered by PPT at 4.7 tons in the upfront Order of July 2008. In addition, the plot turnover ratio has been considered as 30

instead of 12, as per the norms given in the guidelines. Such a high average turnaround ratio is not available anywhere in the world or India. No evacuation model or customer feasibility studies was done to arrive at 30 Turnaround ratio. The parameters as given in the guidelines is considered.

(b). Analysis:

In the proposal of PPT, which culminated into the Upfront tariff Order of July 2008, the PPT had considered stacking capacity of 4.7 Metric Tonnes/ sq.mts and a plot turnover ratio as 30. This was in variance to the norm of stacking capacity of 3 Metric Tonnes/ sq.mts and a plot turnover ratio as 12 prescribed in upfront tariff guidelines. Though in the consultation process forming part of the Upfront tariff Order of July 2008, the users/ bidders had raised objection to the deviations stating that it would be detrimental for the developer, the PPT had categorically stated that it is already handling sizeable quantity of thermal and coking coal with a stacking capacity of 4 Metric Tonnes/ sq.mts. for coking coal and a stacking capacity of 5.4 metric tonnes/ sq.m. for thermal coal has been achieved at its own mechanised coal handling plant. Likewise, the PPT had stated that PPT's own mechanised coal handling plant had achieved a turnover of 21.3. Thus accordingly, the port had considered the mean value of 4.7 metric ton/ sq.m. as the stack height and the plot turnover ratio as 30, based on the specific ground realities and statistical data. Clause 3.2 of the upfront tariff guidelines allows this Authority to make necessary adjustments in the norms prescribed in the guidelines, based on the justification furnished by the concerned Port Trust, keeping in view the port specific conditions.

From the above, it was the conscious decision of the PPT to consider the stacking capacity of 4.7 Metric Tonnes/ sq.mts and a plot turnover ratio as 30 and that there was no error on this aspect. Therefore, there is no merit in the argument put forth by PEQCTL to consider the norms of stacking capacity and plot turnover ratio, as given in the guidelines.

(vii). **Free days:**

(a). Submissions made by PEQCTL:

As per 2008 Tariff Guidelines, free storage days for a coal terminal should be 25 days, and storage charges be applied only after that free period. But in this project, the free storage days provided are only 10 days which violates TAMP 2008 Tariff Guidelines and artificially inflates the storage tariff by 2-3 times. In a recent week cargo inventory at Paradip Port, it indicates a dwell time of 25-30 days with very high plot balance, leading to over ₹ 1000/MT as plot rent.

(b). Analysis:

In the proposal of PPT, which culminated into the Upfront tariff Order of July 2008, the PPT had considered a free period of 10 days, which was in variance to the norm of 25 free days, as stipulated in the upfront tariff guidelines. According to PPT, it was not necessary to allow 25 days free period as stipulated in the norms after the completion of unloading operation, as PPT's own mechanised coal handling plant had achieved a turnover of 21.3. Accordingly, the free period was proposed by PPT at 10 days, taking into account the higher turnover ratio of 30 as proposed by the port. It is noteworthy that 25 days free period as stipulated in the norms is irrespective of whether the coal terminal is export oriented or import oriented. Clause 3.2 of the upfront tariff guidelines allows this Authority to make necessary adjustments in the norms prescribed in the guidelines, based on the justification furnished by the concerned Port Trust, keeping in view the port specific conditions.

In the questions raised by various prospective bidders during the pre-bid meeting (which forms part of the Concession Agreement signed by PPT with PEQCTL), the PPT has in response to some query, has reported that the free period is 10 days, considering the free days prevailing in its then existing coal export terminal.

From the above, it can be seen that it was the conscious decision of the PPT to consider the free period of 10 days. Thus, it is incorrect on the part of PEQCTL to state that the PPT had not given any reasons to consider the free period of 10 days. Therefore, since there was no error on this aspect, there is no merit in the

argument put forth by PEQCTL now to consider the free days as per the norm prescribed in the guidelines.

Nevertheless, it is relevant to state that the rates approved by this Authority are ceiling rates and the operator can charge lower rate. That being so, the PEQCTL has full flexibility to give more free days than the prescribed 10 days.

As regards revenue share payable by the PEQCTL to the PPT, it is to state that the MOS vide its letter No. PD-13/1/2018-PPP cell dated 11 July 2018 has prescribed criteria for classification of PPP project as Stressed Project by Major Port Trusts. The said letter also prescribes the mechanism for payment of revenue share when the storage charge is rationalised i.e. when the storage charge is reduced or free period is increased for stressed PPP project. The principle enumerated in the said letter is that the BOT operator shall pay revenue share at the agreed rate as per the Concession Agreement on the actual revenue from storage charge or revenue share calculated on the ARR from the storage charge estimated in the original Order after applying applicable annual indexation, whichever is higher. In fact, the MOS in its said letter dated 11 July 2018 has referred to this Authority's letter dated 11 September 2015 wherein this Authority has recommended to the MOS on the similar line in the case of Visakhapatnam Port Trust (VPT) for one of their projects pertaining to high storage charge.

Thus, the PPT and the PEQCTL may, as regards revenue share payment on storage charge, mutually discuss and consider to adopt the mechanism prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 for stressed projects.

(viii). **Mix of Capesize and Panamax vessels:**

(a). **Submissions made by PEQCTL:**

In TAMP order, while calculating storage and other terminal capacities, it is assumed that 80% of the cargo will be in Cape size and 20% of the cargo in Panamax size of vessel. In reality, the depth of EQ 1, 2 and 3 berths is only 15 Meters, and terminal is not yet Cape compliant i.e. it does not have sufficient draft to handle Cape vessels yet. Thus, the vessel mix of Capesize and Panamax vessels at 80:20 is not correct.

(b). **Analysis:**

In the Upfront tariff Order of July 2008, upfront tariff caps were fixed by considering the vessel mix of Capesize and Panamax vessels at 80:20 respectively. As brought out earlier, the port itself had chosen to adopt its own tariff as base to arrive at the Reference tariff for the Mechanisation of EQ – 1, 2 and 3 berths and the Guidelines also did not require this Authority and there was no reason for this Authority to delve deep into the details of the facility proposed to be developed by PPT. The tariff is given upfront, even before the project is bid out. In such a scenario, there is no scope now to review the terminal capacity. Therefore, this Authority is not in a position to consider the argument put forth by PEQCTL in this regard.

(ix). **Storage Charges:**

(a). **Submissions made by PEQCTL:**

TAMP has fixed the tariff for this project by order no. TAMP/12/2014-PPT in which TAMP has applied 26.15% WPI Indexation on tariff notified in 2008. However, TAMP and Port Trust had erroneously added "Per day Per MT" in storage charges instead of "different period groups", which inflated the storage charges by 500% over and above the 26.15% WPI Indexation, without any reasoning and basis. The said error has led to application of inflation twice and cumulative inflation index over 630% for the storage charges. Due to such abnormal storage charges, no customer is willing to sign a cargo handling agreement with us, which is a very alarming situation. The charges specified are unprecedented for storage in the PPP ports anywhere in India and abroad, and have no rationale.

(b). Analysis:

(i). In the Order dated 14 July 2008, which has formed the base for prescription of Reference tariff for the coal berth vide Reference tariff Order dated 21 February 2014, the unit of levy for storage charges for handling coal was prescribed on 'per tonne' basis only. However, while seeking approval for prescription of indexed Reference Tariff based on the July 2008 Order, the PPT had proposed the unit of levy for storage charges on 'per tonne per day' basis, which crept into the Indexed Reference tariff Order dated 21 February 2014, unintentionally.

(ii). The table as given below, brings out this position:

Particulars	Unit of levy of storage charges	Rate for first five days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for sixth day to tenth day for the balance cargo	Rate for 11th onwards for the balance cargo
Approved vide Order dated 14 July 2008	Rate in ₹ per tonne	12	24	48
Approved vide Order dated 21 February 2014 after applying indexation factor of 26.15%	Rate in ₹ per tonne per day	15.14	30.28	60.55

Thus, in the Order dated February 2014, though the storage charges were prescribed after applying an indexation factor of 26.15% over the storage rates approved vide the July 2008 Order, the unit of levy of storage charges was prescribed on 'per tonne per day basis', instead of 'per tonne' basis. The said error was not noticed by this Authority or by anyone else at the relevant time. It is only when it is about to be implemented, it has come to light.

(iii). The PEQCTL during the joint hearing has rightly enumerated consequences of such error by an illustrative case, as brought out earlier in this agenda note. As per the indexed storage rate as of the year 2020-21 at ₹ 17.21 per tonne per day, ₹ 34.43 per tonne per day and ₹ 68.86 per tonne per day for the third slab period after the free dwell time of 10 days, based on a day wise cargo consignment of 3350 tonnes per day for 30 days for being shipped on the 31st day, the user will have to pay storage charges after availing free storage period of 10 days amounting to ₹ 3.34 crores, when the storage amount is calculated on the basis of "per tonne per day", as against the storage charges of ₹ 62.16 lakhs, when the storage amount is calculated on the basis of "per tonne" basis. Such result was never contemplated by Tariff Guidelines of 2008.

(iv). Thus, if, the operator is allowed to levy the storage charges on "per tonne per day" basis, an amount of ₹ 3.34 crores would accrue to the operator as per the illustrative example given above; the PPT would also be entitled to receive revenue share on the amount of ₹ 3.34 crores. It will be an unjust return to the operator as well as the Port, at the expense of the port users which cannot be permitted. Terminals are not operated for generating revenue in the form of storage charges.

(v). Moreover, the apportionment of revenue requirement from storage charges is only 1% of the total 100% revenue requirement to operate the terminal, as per the upfront tariff fixation guidelines of 2008. While fixing the upfront tariff in July 2008, the revenue requirement to the tune of ₹ 131 lakhs towards storage charges was proposed to be recovered by levy of storage charges at the rate of ₹ 12/-, ₹ 24/- and ₹ 48/- per tonne respectively, from levy of storage charges between 11th to 15th day, 16th to 20th day and 21st & beyond from the cargo that is remain after providing for 10 days free period. However, from the workings furnished by PEQCTL, the PEQCTL has established that by levying the indexed storage charges on per tonne per day basis, it would earn substantially enormous storage income and would end up earning more than the permitted 16% return. The levy of storage charges on per tonne per day basis would lead to the PEQCTL as well as the PPT earning unjust return on capital employed, at the cost of the port users.

(vi). Since the PPT had invited bids specifying the Order no. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014 wherein the unit of levy of storage charges is “per MT per day”, the contention of the PPT is that change in the unit of levy of storage charges from “per tonne per day” to “per tonne” would be construed as post bid change. In this regard, the PEQCTL has stated that TAMP 2008 Guidelines is main reference point for setting up of tariff for PEQCTL, and same cannot be breached by PPT, TAMP or PPP Operators by way of errors, misunderstanding or whatsoever the reason is, irrespective of whatsoever the stage it is i.e. before the bidding or after the bidding. It is noteworthy that Order of February 2014 was just an adoption of tariff fixed vide July 2008 Order, after applying the applicable indexation factor and nothing else and that while prescribing the storage charges, an error has crept in the prescription of unit of levy of storage charges, which needs to be rectified.

(vii). There can be a view that Clause 2.8 of the upfront tariff setting guidelines of 2008 issued by the Ministry of Shipping (MOS) under Section 111 of the Major Port Trusts Act stipulates that the upfront tariff once determined by this Authority is subject to only indexation during the entire project period of 30 years and do not lend any scope to revise the upfront tariff fixed by this Authority during the project period. In this regard it is to state that in the case in reference, no change whatsoever, is effected to the upfront tariff fixed in the year 2008 and adopted as indexed Reference tariff in the year 2014. Only an anomaly, which had crept in the Reference tariff Order of February 2014 is being rectified. This rectification, in no manner, should be construed as amounting to revision of the upfront/ reference storage charges, approved by this Authority in July 2008/ February 2014.

(viii). Incidentally, in this connection, it is noteworthy to draw reference to similar matters arising in another Major Port viz., Visakhapatnam Port Trust (VPT) as well as with another operator at PPT viz., JSW Paradip Terminal Private Limited (JPTPL).

(a). Incase of VPT, after having the upfront tariff fixed for the West Quay - 6 (WQ-6) Berth in the Northern Arm of inner Harbour of VPT, the VPT awarded the development of the WQ-6 berth to West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) on DBFOT basis. Thereafter, the WQMPL approached this Authority for notification of SOR in its name. The SOR was notified in the name of WQMPL. Subsequently, WQMPL filed a Writ Petition No.28595 of 2017 in the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and State of Andhra Pradesh, seeking interference of the Hon'ble Court, interalia, with the prayer to reduce storage charges prescribed in case of WQMPL. The Hon'ble High Court in its Order dated 14 December 2017 directed this Authority to consider and dispose of the WQMPL's representation. In compliance of the Order of the Hon'ble High Court, this Authority, after consultation with the VPT, vide its Order

no. TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018, had considered the representation of the WQMPL and prescribed the storage charges by dividing the earlier notified storage charges by 7 days, so as to prescribe storage charges on per tonne per day basis.

(b). Similarly, after having got a Reference tariff fixed for a new iron ore berth to be developed at PPT, the PPT awarded the Project to JPTPL on DBFOT basis. Thereafter, the JPTPL approached this Authority for notification of SOR in its name. While doing so, the JPTPL had made a request to rectify an error in the storage charges as notified in the Reference tariff Order, by prescribing the unit of levy of storage charges as 'Rate in ₹ per ton' instead of 'Rate in ₹ per MT per day'. After following the consultation process, this Authority vide its Order no. TAMP/54/2019-JPTPL dated 20 February 2020 has rectified the error in the prescription of the unit of levy of storage charges, while notifying the SOR in the name of JPTPL.

(ix). Infact, while disposing of the proposal of JPTPL as stated above, the PPT during the consultation process had stated that prescription of unit of levy as 'per tonne' for the JPTPL project will have ramifications on the PPP projects relating to mechanization of EQ-1, 2, 3 berths at PPT and development of new coal berth to handle coal imports at PPT vide tariff Orders dated 21 February 2014 and 22 January 2017 respectively. However, this Authority while disposing of the proposal of JPTPL as stated above had categorically stated that the said contention of PPT cannot act as a hindrance to rectify error in the prescription of storage charges at JPTPL. If an error has crept in the prescription of storage charges in the tariff Orders dated 21 February 2014 and 22 January 2017, the said error may have to be examined and rectified in consultation with PPT, when the concerned operators approach this Authority on the matter.

(x). In view of the above position, this Authority is inclined to rectify the error in the unit of levy of storage charges. The rectification can be done in two ways:

(a). Prescribe the unit of levy of indexed storage charges at '₹ per tonne',

OR

(b). Considering that the storage charges are prescribed for a slab of 5 days, the proposed indexed storage charges is divided by 5 and the unit of levy of indexed storage charges is prescribed at '₹ per tonne per day'.

In this regard, given that the storage charges are prescribed on "₹ per tonne per day" basis, across the SOR of all the Major Port Trusts and Private Terminals operating thereat, it is appropriate to prescribe the storage charges on "per tonne per day" basis, as a uniform prescription. The storage schedule contains 3 chargeable slab periods after the free dwell time. Each of first two chargeable slabs have 5 days dwell time. The third slab starts from 11th day onwards (after the free period) for an indefinite period. If the cargo continues to stay in the storage yard beyond the first two chargeable slab periods, and if the unit of levy is prescribed as "per tonne", it is likely that the users may continue to occupy the precious port premises for a longer period, given that irrespective of the period for which the cargo stays in the port premises, the users are liable to pay fixed storage charges for the quantity of cargo lying in the port premises. In such an instance, prescription of storage charges on per tonne per day basis, may discourage an user to utilize the port area as Storage yard for longer period and thereby act as a deterrent.

Thus, incase of PEQCTL, this Authority is inclined to prescribe unit of levy for the storage charges on 'per tonne per day' basis, keeping in view the prescription of unit of levy of storage charges in all other major ports and BOT operators operating thereat.

(x). While responding to the comments of PPT, the PEQCTL has stated that if permitted by this Authority and PPT, it will not charge storage charges from port users anything more than 1% of total revenue, unless otherwise forced by Authority or PPT to charge such tariff. Hence, the PEQCTL has requested this Authority to review the storage charges and other applicable clauses, and pass an order restricting the PPT to demand revenue share from PEQCTL based on only 1% of the total Revenue as total storage charges, which it is entitled for, given that as per the Guidelines, PPT does not have any right to demand revenue share more than 1% as storage charges.

In this connection, as already stated earlier, the MOS vide its letter dated 11 July 2018, while prescribing criteria for classification of PPP project as Stressed Project by Major Port Trusts, also prescribe the mechanism for payment of revenue share when the storage charge is rationalised i.e. when the storage charge is reduced or free period is increased for stressed PPP project. The principle enumerated in the said letter is that the BOT operator shall pay revenue share at the agreed rate as per the Concession Agreement on the actual revenue from storage charge or revenue share calculated on the ARR from the storage charge estimated in the original Order after applying applicable annual indexation, whichever is higher. Thus, as regards revenue share payment on the storage charges, the PPT and the PEQCTL may mutually discuss and consider to adopt the mechanism prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018.

10.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of minds, this Authority is inclined to issue a Corrigendum rectifying the error in the prescription of the levy of storage charges. Thus, the storage charges prescribed at Section 2.2 in the Scale of Rates approved vide Order no. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014, are replaced with the following:

“

(Rate in ₹ per MT per day)

SI. No.	Commodity	Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 6 th day to 10 th day for the balance cargo	Rate for 11 th day onwards for the balance cargo
1.	Thermal Coal	3.03	6.06	12.11

“

10.2. The PPT is advised to take note of the above amendment.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.III/4/Exty./389/2020-21]